17.39 hrs.

MOTION *RE.* FOOD SITUATION AND SITUATION ARISING OUT OF DROUGHT CONDITIONS—*contd.*

श्री प्रबल सिंह (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे सामने आज खाद्य समस्या है उस सम्बन्ध में मैं आपसे कहूंगा कि यह जो खाद्य समस्या का प्रश्न है यह हम लोगों का और सरकार का पैदा किया हुआ है । सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं अगर उनको न अपनाया गया होता तो आज यह समस्या हमारे सामने न होती ।

17.40 hrs.

[SHRI V. C. SHUKLA *in the Chair*]

आज हमारे खाद्य मंत्री बताते हैं कि देश में अकाल है । मैं खाद्य मंत्री जी से पूछूंगा कि देश में अकाल कब से नहीं है । आज कई वर्षों से देश में अकाल चला आ रहा है और पिछले दो वर्ष से तो म खाद्य मंत्री जी का और प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं कि देश की खाद्य समस्या बहुत विकट और जटिल होती चली जा रही है, इस को ठीक ढंग से सुलझाना चाहिए, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया है । हम ने देखा है कि पार साल भी, जब कि फ़सल अच्छी हुई, एक प्रान्त में गेहूं अथवा चावल तीस रुपये मन बिका और दूसरे प्रान्त में अस्सी रुपये मन बिका । आखिर इस का मतलब क्या है ? इसका मतलब यही है कि वितरण की व्यवस्था दूषित है, वितरण ठीक तरह से नहीं होता है । अगर गल्ले पर कंट्रोल न होता और स्टेट्स में खुले तौर से उसका आवागमन होता, तो आज यह हालत न होती । हमारे देश में गल्ला काफ़ी है, लेकिन उसका बंटवारा ठीक ढंग से नहीं हो रहा है । किसी स्टेट में ज्यादा गल्ला है और किसी में कम गल्ला है । अगर गल्ले का बंटवारा ठीक तरीके से हो, तो उस के मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी । और गल्ले का ठीक बंटवारा व्यापारियों के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि व्यापारी बहुत कम मुनाफे पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गल्ला लाता ले जाता है, जिस का नतीजा यह होता है कि सारे देश में एक सा भाव रहता है । जिस तरीके से पानी ऊंची सतह से नीची सतह की तरफ़ बहता है और उसका लेवल एक जैसा हो जाता है, उसी तरह व्यापारी का काम है कि गल्ले को देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जा ठीक भाव पर उसके वितरण की व्यवस्था करे ।

आज सरकार चाहती है कि व्यापारियों को इस व्यवसाय से निकाल दिया जाये और स्टेट ट्रेडिंग लाया जाये । मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि स्टेट ट्रेडिंग इतना नाकामयाब साबित होगा कि उस से देश में क्रेग़ोस हो जायेगा, मुसीबत आ जायेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किये जा रहे हैं, उन में सिवाये ज़्यादा खर्च और नुक्सान के कुछ नहीं होता है । हमारे देश में इस समय 70 पब्लिक अंडरटेकिंग्ज चल रही हैं, जिन में से सिर्फ़ 13 को फ़ायदा होता है और बाकी 57 को नुक्सान हो रहा है । इसकी वजह यह है कि जिस काम को करने वाला आदमी अच्छा और ईमानदार है, वहां तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन जिस काम को करने वाला स्वार्थी और आरामतलब है, जिस को सिर्फ़ पैसा बनाने से मतलब है, तो वहां नुक्सान होता है । इसीलिए हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में काफ़ी नुक्सान हो रहा है ।

मिसाल के लिए दिल्ली मिल्क स्कीम में सवा तीन करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम लगाई गई, लेकिन 1961 तक उस में सवा करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ है । इस से यह प्रकट होता है कि गवर्नमेंट के जितने काम हैं, उन में ओवरहेड चार्जिज बहुत ज्यादा होते हैं, जिन को वह काम या वह अंडरटेकिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते । मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाये जा रहे काम में जो खर्च होता है, एक व्यापारी उस के दस परसेंट में ही काम चला सकता है ।

अगर हम अपने देश की खाद्य समस्या को हल करना चाहते हैं—मैं समझता हूं कि हम सभी की यह इच्छा है—— तो हम को कंट्रोल हटा देने चाहिए और गल्ले के खुले आवागमन की अनुमति देनी चाहिए । हम देखेंगे कि तब ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी कि कहीं तीस रुपये मन गेहूं बिकता है और कहीं अस्सी रुपये मन ।

वर्तमान खाद्य संकट का एक कारण यह भी है कि हमारी सरकार ने खेती की उपज बढ़ाने की तरफ़ ध्यान नहीं दिया है । इसी कारण हालांकि हमारी सरकार पिछले अठारह सालों से खाद्य समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन, जैसी कि कहावत है, मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों ज्यों दवा की । पिछले अठारह बरसों में हम सैकड़ों करोड़ रुपये का गला बाहर से मंगा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश की खाद्य समस्या हल नहीं हो पाई है जब कि हमारा देश एक कृषि-प्रधान देश है ।

आखिर इस बात का रहस्य क्या है कि हमारी खाद्य समस्या हल नहीं हो पाती है ? मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गवर्नमेंट ने एक ग़लत पालिसी अख़्त्यार की हुई है, जो कि अटर फ़ेल्युर साबित हुई है । मंत्री महोदय ने टोटल राशनिंग और लैवी की घोषणा की है । अगर ऐसा किया गया तो देश में कैओस हो जायेगा, देश पर मुसीबत आ जायेगी, जिस को हम सम्भाल नहीं सकेंगे, क्यों कि अगर जनता को खाने को नहीं मिलेगा, तो वह क्या करेगी ? मरता क्या न करता । गवर्नमेंट एक व्यक्ति के लिए दस या आठ औंस की जो मात्रा निश्चित करने जा रही है, उससे लोगों का गुज़ारा कैसे होगा । कुछ समय के लिए तो इस को बर्दाश्त किया भी जा सकता है, लेकिन अगर लगातार ऐसा होता रहेगा, तो काम कैसे चल सकता है ?

धनी आदमी को अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि वे दूध और फल वग़ैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग़रीब आदमी कैसे अपना गुज़ारा करेगा । आज से कुछ बरस पहले जब हम यह सुनते थे कि विलायत में एक रुपये का एक सेर मैदा या आटा मिलता है, तो हम लोग ताज्जुब करते थे कि वहां के लोग कैसे गुज़ारा करते होंगे, हालांकि वहां एक आदमी की आमदनी पंद्रह, बीस रुपये रोज़ है । लेकिन हमारे देश में तो एक आदमी की आमदनी तो दो, तीन, चार रुपये रोज़ है । अगर यहां भी एक रुपये सेर आटा मिलता है, तो गृहस्थी कैसे अपना गुज़ारा कर सकता है ? हम लोग जनता से कन्टेक्ट करते हैं और इसलिए हम लोगों को मालूम है कि लोग किस तरह दिन काट रहे हैं और क्या उन के ख़यालात हैं । इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इस फ़ैसले पर पुनर्विचार करें ।

मैं ने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी को लिखा है कि जब शासन इस काम को पूरा नहीं कर सकता है, तो उस को क्या ज़रूरत है इसे अपने ऊपर लेने की । इस काम को स्टेट्स के लिए छोड़ देना चाहिए । स्टेट्स इस काम को करें । गल्ले का खुला आवागमन हो और व्यापारियों को यह काम दिया जाये । जब से चीन और पाकिस्तान का हमला हुआ है, जनता की हमदर्दी सरकार के साथ है । व्यापारियों ने भी यह तय किया है कि हम गवर्नमेंट को पूरा सहयोग और मदद देने के

[श्री अचल सिंह]

लिए तयार हैं । उन की फ़ेडेरेशन ने प्राइम मिनिस्टर और हम लोगों को एक सर्कुलर भेजा है, जिस में कहा गया है कि हम हर एक काम करने के लिए तैयार हैं । गल्ले के जितने व्यापारी होंगे, उन के नाम रजिस्टर्ड होंगे, वे लाइसेंस्ड होंगे और रजिस्टर में यह इन्दराज होगा कि कितना माल आया, कितना बेचा गया और कैसे बेचा गया । इस प्रकार व्यापारियों के द्वारा काम किये जाने से कोई गड़बड़-घोटाला नहीं हो सकता है । इसलिए यह आवश्यक है कि उन का सहयोग लिया जाना चाहिए । मेरा विश्वास है कि अगर हम व्यापारियों की फ़ेडेरेशन का सहयोग लें, तो स्थिति बहुत सुधर जायेगी ।

आज की हालत के बारे में कहा जाता है कि बड़ा भारी अकाल है । मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान इतना बड़ा देश है, जिस में पन्द्रह स्टेट्स हैं । यह बिल्कुल नेचरल है कि इतने बड़े क्षेत्र में कहीं सूखा हो, कहीं वर्षा हो और कहीं अकाल हो । सारे देश में एक जैसी स्थिति कैसे हो सकती है ? इस प्रकार की हालत हमेशा होती आई है और इस देश में अकाल पड़ते रहे हैं, लेकिन होता यह है कि सरप्लस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से डेफ़िसिट स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में गल्ला आ जाता है और काम चल जाता है । लेकिन गवर्नमेंट ने अब देश में कई ज़ोन बना दिये हैं, एक जगह से दूसरी जगह गल्ला नहीं लाया जा सकता है गवर्नमेंट राशनिंग और कंट्रोल जैसे कदम उठा रही है । इस कारण यह कठिन स्थिति पैदा हो गई है ।

मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि अगर अपने देश को केआस से बचाना है, तो हम को मौजूदा पालिसी में आमूल परिवर्तन करना चाहिए । और अगर हम ने ऐसा न किया तो आप देखेंगे कि चार छः महीनों में क्या हालत होगी । राशनिंग की व्यवस्था होने पर लोगों को क्यू बना कर घंटों खड़े रहना पड़ता है और राशन को बारह औंस से दस औंस, आठ औंस और छः औंस तक घटाया जा सकता है । एसी स्थिति में जनता का काम कैसे चल सकता है ? अगर जनता को सरकार से खाने-पीने की चीजें नहीं मिलती हैं, तो वह क्या करती है ? मुझे खुशी है कि हमारे देश की जनता महात्मा जी के सिद्धान्तों के प्रभाव से हिंसा के काय नहीं करती है । अगर कोई दूसरा देश होता, तो एसी हालत में न जाने क्या हो जाता ? मैं तो यही कहूंगा कि ईश्वर हम को सद्बुद्धि दे । मैं प्रधान मंत्री जी और मंत्री महोदय से कहूंगा कि हम को अपनी नीति में आमूल परिवर्तन करना चाहिए, जो समय के अनुकूल हो । तभी हम इस समस्या को हल कर सकते हैं, वर्ना हालत बहुत खराब हो जायेगी, जिस को हम सम्भाल नहीं सकेंगे ।

सभापति महोदय : श्री के० सी० पन्त ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि हम कब तक बैठने वाले हैं, कितने माननीय सदस्यों को बुलाया जायेगा और हमारे दल के माननीय सदस्य को कब बुलाया जायेगा ।

सभापति महोदय : जब तक वे सब माननीय सदस्य नहीं बोल लेते हैं, जो कि बोलना चाहते हैं, तब तक हम बैठने के लिए तैयार हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हमारे दल के सदस्य को कब बुलाया जायेगा ?

Shri K. C. Pant (Naini Tal): Member after Member who has participated in this debate has expressed his or her anxiety about the serious food situation facing the country and it is generally recognised on all hands that this is the result this year of the vagaries of the monsoon. But the serious point to consider is that so many years after independence our food production is still at the mercy of the vagaries of the weather. That is a serious matter, and in discussing this problem, we have necessarily to go over the ground that has already been covered and to try to find out where we have slipped up. When we look back over the years, we find that our agricultural problems have been diagnosed again and again; the problems are known and so are the remedies. The only question is how those remedies are to be applied. It is in the field of implementation that the failure has been most obvious and most flagrant.

The problems can be broadly divided into two sectors: technical problems and administrative problems. I do not want to go into the details, but it is obvious that if you take even such a thing as irrigation about which must has been said in the House, the concept of irrigation at the moment in India is to prevent plants from drying up. There is no scientific attempt to supply the amount of water at the intervals at which a particular crop requires it. It is one thing to supply water at random and it is quite another to supply it according to the needs of the crop.

Similarly, there is the question of the use of fertilisers: chemical fertilisers and others. It is not a question simply of applying any chemical fertiliser. It is a question of applying those plant nutrients which the crop needs, and to supplement the plant nutrients which the crop can draw from the soil. Similarly, there is the question of supplying the farmer in the country with an alternative fuel so that he can use his cowdung for manure. Then there is the question of an extension service which could act as a bridge between the research laboratories and the field. These are all known problems, but over the years, we have not really made a dent on these problems.

On the administrative side, there is the question of land reform. We want the land to go to the tiller; we are committed to that idea, and yet, there are many pockets in which that is not a reality. We all know how much food is consumed by rats and other pects; if only that food could be saved, it would probably get us over the hump in the food situation. But we have not tackled this problem with the seriousness it deserves.

There is the question of improved seeds which has just received some particular attention, but over the years we have failed to establish any suitable machinery for the distribution of improved seeds. Then there is the question of credit; there is the question inter-departmental co-ordination and so on and so forth. These are all the administrative problems that have been diagnosed long ago, but to which no solution has yet been found. Therefore, we have got to look at this problem from the point of view of implementation. I feel that unless we take a very objective, dispassionate and scientific approach to these problems, solutions will not be easy to come upon. I was very happy this morning to read in the newspapers that the Food Minister has suggested that in technical departments, the decisive voice should be that of the technical persons. It is one of the healthiest statements that has come from a Minister in recent times, and unless technical opinions receive the weightage they deserve, I am afraid that problems which are essentially technical in nature will be very, very difficult to solve, as has been the experience in the past years.

[Shri K. C. Pant]

The second thing needed now is, of course, an implacable will and a burning passion to bull-doze our way to a break-through on the food front. What we need now is action; we need ruthlessness in dealing with inefficiency and procedural delays.

Mr. Chairman, the framework of our food problem is roughly this: One-third of our total production finds its way to the markets and that is the marketable surplus, and that marketable surplus has to feed about 30 per cent of the population which is wholly dependent on this marketable surplus; and this 30 per cent or about 14 crores increases every year by one crore. Therefore, if the marketable surplus does not keep pace with the increase in population, there is immediate scarcity. If we really want to make a breakthrough on the food front, we must not only have a marginal excess of supply over demand but we should have a big excess so that we can create a buffer-stock and have enough of a buffer-stock to tide over the lean years. That is really the essence of the solution for which we have to aim.

Last year we had a bumper crop. Last year 24 lakh tons of rice were distributed; 15 lakh tons were procured, though the target was 19.5 lakh tons, and 7 to 8 lakh tons were imported. So, the total that was distributed to the States was 24 lakh tons. Even then the deficit States were not happy. What is the position this year? The kharif crop has been badly damaged by lack of rain during the monsoon. So, the rice crop is 10 per cent lower, i.e. 3 to 4 million tons less. Similarly, the production of jowar, bajra, maize, etc. may also be lower by another 3 to 4 million tons. The *rabi* crop is uncertain. So, as matters stand now, I think an optimistic estimate would be that procurement may reach about 8 to 10 lakh tons. Imports may be of the order of 5 lakh tons, because we lack foreign exchange. So, even on an optimistic estimate, in the field of rice the gap can be expected to be something of the order of 9 to 10 lakh tons. This is a fairly serious gap. So, we have to be prepared in the coming year for a fairly serious shortage. I do not see any way of improving the situation so far as availability is concerned. What we have therefore to concentrate on is to ensure that the distribution is equitable.

From that, we come to the point of considering whether the government's present policy is likely to achieve that equitable distribution. At present, the basic planks of our food policy are firstly, a zonal system in which each State is cordoned off, secondly, monopoly procurement and thirdly rationing and government distribution. So far as the zonal system goes, the implication of the zonal system, of each State being cordoned off, is that the responsibility for feeding the deficit States falls squarely upon the Centre, because all the deficit States have been cut off from their traditional sources of supply. We want to meet this responsibility by introducing monopoly procurement in certain States. This could be done with advantage if the Government had two months' stocks, because it will take two months for the Government to go into the market and get the supply. But do they have these stocks? Another aspect is that when the Government is the sole buyer in respect of the foodgrains, it can only take foodgrains from the market. It does not levy. If some farmer or trader holds back the foodgrains from the market, the Government cannot get the foodgrains. In the meantime, it has to shoulder responsibility to feed the people.

Similarly there is the question of levy. But it is a very difficult matter to collect levy from hundreds of thousands of farmers, who consider that a levy deprives them of a reasonable price. Therefore, there are various shortcomings in the present scheme. There is disparity in avail-

ability and prices and there is a feeling that certain States have it much better than others. Nevertheless, I do feel that a certain amount of regulatory control on inter-State movement of foodgrains is necessary in a scarcity. But the point is whether it is really necessary to cordon off each State. In this respect, without going into details, I would endorse the suggestion made by Mrs. Sharda Mukerjee that we should revert to the pre-1964 position when there were three large zones—the southern zone, the eastern zone and mid-central zone—and the experience was very good. If we go back to that, I feel the situation in the south, particularly in Kerala and Mysore which are facing extremely difficult situations, will be eased to a considerable extent. And, what is most important, the Centre's commitments and responsibilities will be reduced, because the Centre can obviously meet that responsibility only if it can procure the grain and as matters stand, for it to procure the grain which it will have to distribute is extremely unlikely. For the Centre to assume a responsibility that it cannot discharge would be fatal. The only argument that can be used against this is that the trade will take advantage of this kind of liberalisation, because once you create these bigger zones, naturally the trade will operate within the zones and it can be said that in a condition of scarcity, the trade will tend to hold back the stocks and the prices will go up causing suffering to the people. That is a fact which we have to recognise. The answer is, our Food Corporation has been created specifically for the purpose of undertaking this kind of trade operations, of going into the market in surplus States, buying after the harvest and distributing the produce in the deficit States. This Food Corporation must step into the picture and see to it that these unsavoury practices cannot be indulged in and prices cannot be forced up.

18 hrs.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Mr. Chairman, I am very glad that Shri Pant has preceded me and we have listened to a very reasoned and very well thought out speech containing some suggestions very useful for the Ministry to take into consideration.

I am not going to discuss this question from an all-India point of view; I am particularly concentrating my attention upon the position of Vidarbha in regard to this matter.

Sir, the drought of a few months, the absence of rain for a few months, is not altogether a new phenomenon in India. Cultivation in this country merely depends upon rains, but very often it happens that certain regions which need rains do not have it and therefore conditions of scarcity do occur. But in my whole life for about 85 years I have seen one thing. We have seen famines occurring in the whole of India, in different parts of India, but so far as Vidarbha is concerned, so far as those eight districts are concerned, even during those worst days there was no famine as such in those eight districts. They were in such a position that they could feed themselves with what they grew and send out something to other States. That was the position, I remember, in the famous year of 1896.

But now, this year, what I find is that the people of Vidarbha are terribly afraid of the situation. That is the position there. The main reason for this, in my opinion, is that formerly the cultivators used to gather the crop and keep some stock with them in surplus for use in the next year in addition to what was required by them for the year, whereas on account of certain conditions of scarcity of food in the country for the last so many years, in spite of better crops, there is no such thing as stocks of grains with the farmers on which they can fall back in the lean months when they would not get any crop at all. That has made them terribly afraid.

[Dr. M. S. Aney]

When they were getting something, using what was required by them for the year and keeping something for use in the next year, what is the reason why that stock has disappeared? My submission is this. On account of the merger of Vidarbha with the whole of Maharashtra which was always a deficit province with the city of Bombay, a big city like that, and the responsibility of feeding the people of that city being on the State Government, the old arrangement on which the cultivators or farmers of Vidarbha were living was terribly disturbed. In the season something happens as a result of which most of the stocks of grain go away from the farmers to big cities like Bombay. The result is that today, I am reliably informed, jowar can be had at a lower price in Bombay while it can be had at a higher price in Birars and other parts of the Vidarbha. Similarly, rice can be had at lower price there than what it can be had at in Nagpur. Why is it so?

The eight districts of Vidarbha which was an economic unit with Chhattisgarh and Narbada region in Maharashtra, so long as this was a part of those territories, we had considered ourselves as self-sufficient. This whole Chhattisgarh and Vidarbha together considered themselves self-sufficient. They grew rice and we grew jowar and other things and the thing was going on all right. That position is changed, as we began fighting for the formation of a linguistic province thinking that it would create cultural unity. That linguistic culture by itself does not give food which is man's prime necessity. All these essential conditions were overlooked in a mad craze, in my opinion—kindly excuse me; I am using this word—for linguistic considerations behind which was concealed an expantionist tendency on the part of persons which had led to the result that these economic difficulties are coming and nobody can come to the help of the suffering people.

Last year promises were given that they were making collections of jowar and everything from the farmer so as to have a good stock. The Chief Minister made that promise; every Minister made a promise. What was the result? As you know, although you represent in this House a constituency in Madhya Pradesh, the position was that the local government almost failed to make any collection from the farmers. This is the position. The conditions of scarcity of food and famine are felt most keenly in these eight districts and the new set-up is unable to give any relief to these districts.

Secondly, we simply relied upon rain water. In the whole of Vidarbha there was no irrigation at all—absolutely nothing except a place called Kayar from where there was irrigation which was sufficient to irrigate a few thousand acres only. There was no irrigation at all. We thought that being merged with Maharashtra and with their big plans we may have our fair share of irrigation also. What we found was that the first thing that was done by the Maharashtra Government was to rule out the Bhandara scheme over which more than Rs. 14 lakhs were already spent and which was to cost Rs. 14 crores or something like that. After that no big scheme of irrigation for the whole of Vidarbha was taken up which should have been sufficient for the whole of Bhandara District which is the best rice growing district in Vidarbha. Later on I brought this fact to the notice of my hon. friend, Dr. Rao, the Minister of Irrigation and Power. He surveyed that scheme also and said that it could have been improved and made practical; but, anyhow, he did not succeed in doing that.

Ultimately, the second solution found out was that we shall have minor irrigation schemes. I have got a book here—I do not want to take the time of the House by reading the whole of this book—which gives the

irrigation schemes, major, medium and minor, which have been thought of by the Maharashtra Government and which are under their consideration. They are only for three districts, Nagpur, Vidarbha and Bhandara. I say only this much that the schemes have been thought of and they are under consideration. They are said to be sanctioned and the amount that is sanctioned for the whole year is also given there. Let me take one scheme and that will give you some idea as to how these schemes are being worked. There is the Bagh River project. The total amount sanctioned was Rs. 5.34 crores; the actual amount sanctioned was Rs. 50 lakhs for this year and the amount spent is only Rs. 2.23 lakhs. This is the proportion of the work done. I do not know at this rate how many years it will take. Though the minor irrigation schemes have been sanctioned—they are not sufficient—but yet whatever schemes are sanctioned, they are not being properly worked out and they are not being taken up seriously and, therefore, the advantages which even the minor irrigation schemes would have given are denied to the people. That is the position today.

I agree with the complaint which has been made here that in carrying out the work for the improvement of food production, etc., there is no proper coordination amongst the various departments of the Government. I think there ought to be better coordination than what there is today.

The third point that I want to make is that you must try to make full use of the material you get. I want to say something about the supply of fertilisers. The Government may be sincere and anxious to do their best but the people who have to get the work done are not serious at all. I may give an example here. The people of Amraoti district have started a number of cooperative societies, about 21 societies, and they wanted to have fertilisers. They used to get fertiliser from the Bombay factories. But last year, for certain reasons, the Bombay factories could not supply them the fertiliser which they wanted and they were asked to get it from the Calcutta factory—I do not want to give the name of that here—and they got it in gunny bags which were tattered and torn and almost half of it was lost. They could get only half of what they ordered. The report was made. The delivery was taken and the whole of the amount was already paid. Later on, when this matter was brought to the notice of the Government, they made certain enquiries in the matter and the result is that upto this time the matter has not been decided. The poor men have lost about Rs. 20,000. There is nobody to help the farmer. The Manager is there but he is completely indifferent. Therefore, unless you create a sense of responsibility in the staff, through whom you have to get the work done, unless you make them pure and not corrupted, there will not be any improvement in the situation.

Lastly I would say that there should be proper co-ordination. The Minister of Food & Agriculture should see that there is co-ordination not only between his Ministry and the other Ministries but also among the staff, through whose hands the work has to be done.

श्री क० मा० तिवारी (बगहा) : सभापति महोदय, आज खाद्य की जो समस्या है वह कितनी गम्भीर है उसको हम सभी समझते हैं । एक परिवार का भरण पोषण करने के लिए, उसका इन्तिज़ाम करने के लिए एक आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी चिन्ता करनी पड़ती है । फिर 45 करोड़ लोगों का जहां सवाल हो और उनके खाने पीने और भरण पोषण का सवाल हो उसको उपलब्ध करने के लिए कितनी चिन्ता भारत सरकार को और मिनिस्टर को होगी इसका हम अनुमान कर सकते हैं । मैं उनको बधाई देता हूं कि वे इतनी कठिनाई

[श्री क० ना० तिवारी]

के बावजूद इस काम को कामयाबी से कर रहे हैं ।

आज यह समस्या केवल हिन्दुस्तान की ही नहीं है, आज यह दुनिया की समस्या है । खाने के सम्बन्ध में रोम में एक सभा हुई थी जिसकी यह रिपोर्ट है :

"The world food outlook is alarming, with the prospect of serious famines in heavily populated areas during the next five to ten years, Mr. B. R. Sen, Director-General of the Food & Agriculture Organisation warned here today. For nearly seven years, there had been no appreciable increase in food production per head of world population. In the Far East and Latin America, production per head was less than it was 25 years ago."

खेती के साथ इंडस्ट्री का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में वह कहते हैं :

"Crash programmes of industrialisation could not secure economic growth unless based on a parallel development in agriculture."

जहां तक फूड का सम्बन्ध है, यह सवाल आज सारी दुनिया को फेस करना पड़ रहा है । **हिन्दुस्तान टाइम्स** के एडीटर ने "लीन इयर" के शीर्षक में लिखा है :

"The widespread drought conditions in India this year are not peculiar to this country. Several other countries have also been affected by drought in varying degrees. In the southern parts of the African Continent, the vast velds have been stricken by a severe drought and South Africa, an agriculturally rich country, is faced with the prospect of importing foodgrains next year. Kenya is going through a similarly difficult period. In some parts of Australia, the livestock industry has been badly hit by drought. Though China claims a bumper harvest this year, several parts of that country too are faced with a dry spell. All this is bound to affect the world food position adversely."

यह रिपोर्ट है जहां तक आज की फूड सिचुएशन का सवाल है ।

इसी के साथ साथ हमारे देश में वर्षा पूरी न होने के कारण इस साल अन्न का उत्पादन बहुत कम होने का अनुमान है, जैसा कि हमारे फूड मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वह 8 मिलियन टन से 10 मिलियन टन तक कम हो सकता है । जब इस तरह से हमारे फूड मिनिस्टर साहब ने कहा तो माननीय सदस्यों ने कहा कि उन्होंने बड़ा अलार्मिंग स्टेटमेंट दिया है । लेकिन अगर उन्होंने इस बात को यहां पर न कहा होता तो थोड़े दिन बाद जब बजट सेशन आता तो लोग यही कहते कि जो असली चित्र था उसे सरकार ने संसद् से छिपाया । इसलिये मेरे खयाल से उन्होंने यह बड़ा अच्छा किया कि जो उत्पादन के आंकड़े हैं, कि इतनी कमी हो सकती है, उन को हाउस के सामने रखा ।

18.21 hrs.

[SHRI SONAVANE *in the Chair*]

अभी इस बात को कहा गया, कांग्रेस बैंचेज की तरफ से भी और अपोजीशन बैंचेज की तरफ से भी, कि पी० एल० 480 को बन्द कर देना चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, अमरीका, कैनाडा और आस्ट्रेलिया को छोड़ कर या ऐसे देशों को छोड़ कर जिन की आबादी कम है और जमीन ज्यादा होने की वजह से पैदावार ज्यादा है, जो कि अनाज बाहर से न मंगाता हो । यहां तक कि रेवोल्यूशन होने के 40 वर्ष बाद भी आज

रशिया करीब छः मिलियन टन अनाज अमरीका से मंगाता है और 6 मिलियन टन चाइना खरीदता है ।

एक रिपोर्ट **टाइम्स आफ इंडिया** में आई है, जिसका सम्बन्ध कैरो से है, उस में लिखा है :

> 'CAIRO, December 2: 'Talks will begin here on December 6 between the U.S. Ambassador Mr. Lucius Battle and the UAR Deputy Premier in charge of Finance and Economic Affairs for signing a new PL-480 agreement.'.

यू० ए० आर० जहां हर साल खाद्यान्न की पैदावार बहुत ज्यादा होती है वह भी पी० एल० 480 में अनाज मंगाता है । इसलिये जो लोग यह कहते हैं, खासकर ऐसी स्थिति में जब कि आठ से दस मिलियन टन तक अनाज कम होने जा रहा है, कि पी० एल० 480 को बन्द कर दिया जाये, वह ठीक नहीं है । उस से देश का नुकसान होगा । इस से भुखमरी बढ़ जायेगी और लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जरूर पी० एल० 480 का अनाज मंगाये, और अगर दूसरी जगह से भी मिल सके तो वहां से भी मंगाये ।

जहां तक हमारे यहां पैदावार बढ़ाने का सवाल है, हम को एक किताब दी गई है "रिओरिएन्टेशन आफ प्रोग्रैस आफ एग्रिकल्चरल प्रोडक्शन" । उस में करीब करीब सारी बातें दी गई हैं । लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जब सरकार इन सारी बातों को समझती है तब हम लोगों को क्यों यह लिख कर देती है कि इस काम को हम आगे नहीं ले गये । हम ले जायेंगे या सरकार ले जायेगी । अगर सरकार यह समझती है कि यह काम होने चाहियें और उन के होने से ही खाद्यान्न की स्थिति सुधर सकती है, तो यह सरकार का काम है कि वह उस काम को आगे ले जाये, उस को स्वीकृति दे और उस को जितनी तेजी के साथ हो सके रेड टेपिज्म को हटा कर करे ।

इस में एक बात कही गई है खाद्यान्न के सम्बन्ध में, और वह है मछली को ले कर । फिशरीज डेवेलपमेंट के सम्बन्ध में आजादी के अठारह साल बाद इस रिपोर्ट में पेज 15 पर दिया गया है :

> "It has been estimated that it should be possible for India to produce 10 million tonnes of fish (8.5 million tonnes of marine and 1.5 million tonnes of inland) as compared to the existing estimated annual production of 0.8 to 1.4 million tonnes. This shows that there is immense scope for stepping up efforts for increasing fish production. Increase in fish production is necessary not only as a supplementary food but also because of its export potentialities. It is estimated that the requirement of fish for the population in 1966 would be of the order of 7.2 million tonnes. This is based upon per capita consumption of 2½ ozs. for 60 per cent of the total population."

अगर हम 10 मिलियन टन मछली पकड़ सकते हैं तो क्यों अब तक 0.8 से लेकर 1.4 मिलियन टन तक ही पकड़ी गई । इसके लिये कौन जिम्मेदार है । अगर इसके लिये कोई भी जिम्मेदार है तो सरकार है ।

इसलिये मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं । एक कमीशन तो इस बात की जांच के लिये नियुक्त किया जाये कि जितने रुपये स्टेट्स को दिये गये हैं उन का प्रापर यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं, और उसमें अन्दर आफिशल्स और नानआफिशल्स दोनों को रक्खा जाये । साथ ही लांग टर्म और शार्ट टर्म दोनों प्रोग्रामों पर जोर दिया जाये । क्राप पैटर्न की जो स्कीम दी गई है उस को लागू किया जाये और देखा जाये कि जो

[श्री क० ना० तिवारी]

काप पैट" है वह पूरी तरह सफल हो । जहां तक ऐग्रिकल्चर सर्विस का सवाल है मेरा ख्याल है कि उस को सेंट्रल सर्विस होना चाहिये ।

इस के बाद एक और सुझाव द्वारा यह है कि डिपार्टमेंट ग्राफ फूड एण्ड ऐग्रिकल्चर ग्रौर कम्युनिटी डेवेलपमेंट को मिला देना चाहिए ग्रौर तीनों को मिला कर एक कर देना चाहिये ।

इसके बाद मैं शुगरकेन के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि चूंकि ग्रनाज का सवाल ग्राज उठ रहा है इस लिये कि ग्रनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिये किसान ग्रागे नहीं बढ़े हैं । इसी चीज को लेकर महाराष्ट्र में शुगरकेन के प्रोडक्शन पर 25 परसेंट कमी का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है । इसी तरह से यू० पी० ग्रौर बिहार में जो किसान हैं वह लोग भी सोरियल्स ज्यादा बोने जा रहे हैं, गन्ना कम बोने जा रहे हैं, । कि ग्रगले साल फिर गन्ने का सवाल उठेगा । इससे ग्रापका जो बफर स्टाक 7 मिलियन टन का होना चाहिये उस को पूरा करने में कठिनाई होगी ।

ग्रन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि बैंकों ने बफर स्टाक पर एडवान्स देना बन्द कर दिया है इसलिये फूड कारपोरेशन को या एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट को इसके लिये एडवान्स देना या दिलाने का प्रबन्ध करना चाहिये ।

Mr. Chairman: How long would Members like to sit?

Shri Yashpal Singh (Kairana): When work is worship, we must sit till midnight.

श्री हुकम चन्द कछवाय : हमें यह देख लेना चाहिये कि कितने बोलने वाले हैं ।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) पांच पांच मिनट दे दिये जायें ।

Mr. Chairman: The tendency to leave the Chamber after a Member speaks is not healthy. I would request Members who have spoken to continue to sit. Then if the House agrees, we can restrict the speeches to five minutes each.

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : नहीं, दस मिनट । ग्राखिर हम लोगों ने कौन सा पाप किया था कि ग्राप हमको पांच मिनट दे रहे हैं ।

श्री चन्द्रमणी लाल चौधरी (महुग्रा) : मैं ग्रापसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह ऐसा सवाल है जिस पर बहुत से मेम्बर बोलना चाहते हैं । सभापति महोदय, ग्राप यह समझ लें कि चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों या दूसरी पार्टियों के, यहां पर जो हैं इसी लिये बैठे हैं ग्रौर मैं समझता हूं कि उनके ऊपर ग्रापकी मेहरबानी जरूर होनी चाहिए ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : बोलने के बाद यह मेम्बर चले जायेंगे ग्रौर सदन में गणपूर्ति नहीं होगी ।

Mr. Chairman: How many Members would like to speak? I find 11 Members standing. At the rate of 5 minutes, it comes to 55 minutes. Would the House like to sit for another 55 minutes?

Shrimati Laxmi Bai (Vicarabad): Those who were sitting here on Thursday till 7 P. M. and did not get a chance, should be called first.

Mr. Chairman: So, the sense of the House is that we sit up to 7. Let us agree either to sit up to 7 or 5 minutes each and we complete the debate.

Shri Vishram Prasad: Ten minutes each.

Mr. Chairman: All right.

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : सभापति महोदय, देश की खाद्य स्थिति के

खाद्य उत्पादन तथा अकाल के बारे में हमें तीन किताबें मिली हैं। महाराष्ट्र के बारे में खाद्य मंत्री को हमने निवेदन किया है। आज जब हम उस पर विचार करने जा रहे हैं तब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा।

सभापति महोदय, भारत सरकार की नीति यह है कि देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाये। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाए जायें। इसके सम्बन्ध के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाय। भारत सरकार नहीं चाहती कि विदेशों से अनाज मंगाया जाय। लेकिन अगर अनाज की कमी होती है तो विदेशों से अनाज मंगाया जाये। आगे का जो अन्न का संकट है वह बहुत गम्भीर संकट है। अगले वर्ष मार्च के बाद गम्भीर खाद्य संकट पैदा हो सकता है। खरीफ की फसल वर्षा के अभाव में संतोषजनक नहीं है। अनुमान है कि अगले वर्ष कम से कम तीस प्रतिशत अनाज की कमी समूचे देश में होगी। देश में वर्षा की कमी के कारण अनाज, पानी और चारे की भयंकर कमी का दृश्य आ गया है। आगामी वर्ष अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका से जो अनाज मंगाने का प्रश्न है वह यह संकट देख कर मंगाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कृषि उत्पादन के बारे में कोई सुझाव देना नहीं चाहूंगा क्योंकि 12 नवम्बर को इस हाउस ने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें सब बातें दी गई हैं। उसमें यह है कि भारत सरकार किसानों को लाभप्रद तथा उचित मूल्य दिलाना निश्चित करे, किसानों को सस्ती दर पर उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, अच्छे बीज तथा कृषि यंत्र इत्यादि देने की व्यवस्था की जाय। यह रिजोल्यूशन 12 नवम्बर को इस हाउस ने एडाप्ट किया और शासन ने उसको मान लिया है। इसलिये उसके इम्प्लीमेंटेशन करने का काम है। बहुत दफा खाद्य पर चर्चा हुई है। मैं नहीं चाहता कि उस पर और ज्यादा बहस हो।

लेकिन मैं चाहता हूं कि यह एग्रिकल्चर प्रोडक्शन की जो किताब है, उसमें कुछ बातें दी हैं। उसमें दिया है कि कृषि अर्थ व्यवस्था के बारे में देश की एक पालिसी होनी चाहिए। कर्ज जो किसानों को दिया जाता है उसके लिए उसकी जो योग्यता, पात्रता देखी जाती है वह उसके पास कितनी मालियत होती है उस पर निर्धारित की जाती है। मेरा कहना यह है कि कर्ज पाने की योग्यता उत्पादन की सामर्थ्य पर न कि पूंजी और सम्पत्ति के स्वामित्व पर अनिवार्य रूप से आधारित होनी चाहिए। वह कैसी काश्त करता है, प्रोडक्शन कितना बढ़ाता है, ये देखना चाहिए। आज क्या होता है कि जो छोटे काश्तकार हैं, टेनेंट्स हैं, उनको लोन नहीं मिलता है। उनकी तादाद बहुत बड़ी है। अनाज पैदा करने वाले यही होते हैं। लेकिन यह इतनी जो स्कीम्स हैं वह उस पर लागू नहीं होती है। उसको कर्जा नहीं मिलता है और भुवनेश्वर रिजोल्यूशन में हमने यह तय किया है कि हमारी यह पालिसी रहेगी कृषि की कि हमारी ऋण देने की नीति उसकी उत्पादन क्षमता पर निर्भर रहेगी। यह हमारी पालिसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको एडाप्ट करना चाहिये और स्टेट्स को इस तरह का आदेश देना चाहिए।

दूसरी बात सभापति महोदय, यह है कि हर एक चीज का बीमा होता है, अभियन्त्रण का भी बीमा होता है, लेकिन किसान की जो फसल है और उसके पास जो बड़ी बड़ी कीमत के जानवर रहते हैं उसका बीमा नहीं होता। किसान को मौसम की परेशानियां से बचाने के लिए उसकी फसलों और मवेशियों के बीमे का तरीका शुरू किया जाना चाहिए। यह एडाप्टिड पालिसी है। कांग्रेस ने यह पालिसी एडाप्ट की है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है।

तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिलना

[श्री दे० शि० पाटिल]

चाहिए । लेकिन उसको उचित मूल्य नहीं दिया जाता । प्राइस सपोर्ट की जो पालिसी है वह बिल्कुल फेल्योर पालिसी है और यह जो संकट आया है, यह संकट उसीका नतीजा है, वह पालिसी जो भारत सरकार ने एडाप्ट की दस पन्द्रह सालों में उसका यह नतीजा है। सब भाग्य से या दुर्भाग्य से चीन और पाकिस्तान का संकट आया है तो इस वक्त किसान कौन है, किसान अनाज पैदा करने वाला है, इस तरफ हमारा खयाल गया है, नहीं तो अब तक किसान कोई आदमी है यह भी नहीं मानते थे और किसान का जो खेती का धंधा है उसको भी धन्धा नहीं मानते थे । इसी का यह सब नतीजा है ।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं मेरा टाइम बहुत कम है । लेकिन मैं कुछ बुनियादी बातें यहां बताना चाहता हूं । यह फूड पालिसी जो तय हुई है अगले साल के लिए, चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस हुई और उसमें यह तय हुई, नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की जो बैठक होती है उसमें भी इस पर चर्चा होती है और कुछ रिजोल्यूशन होते हैं लेकिन बाद में इन रिजोल्यूशंस पर या जो निर्णय लिये जाते हैं उन पर कोई अमल नहीं करता । हर एक स्टेट वाले बाहर आने के बाद कहते हैं कि अब अपना अपना देखो । यह जो नेशनल पालिसी है, जो नेशनल फूड पालिसी बनाई गई थी उसमें यह तय हुआ था कि भारत का एक राष्ट्रीय बजट रहेगा और यह बजट प्लानिंग कमीशन तय करेगा । लेकिन हर एक स्टेट आता है जो सरप्लस है वह भी अपने को डेफिसिट कहता है और जो डेफिसिट है वह भी डेफिसिट कहता है, इसलिए यह तय हो गया था कि—

"The surpluses and deficits of the different States in the Union will be assessed and periodically revised, if necessary, by the Planning Commission assisted by the Agricultural Prices Commission. The decisions of the Planning Commission will be binding on all States."

लेकिन यह भी नहीं हुआ । दूसरी बात जो इसमें कम्पलसरी प्रोक्योरमेंट करने की थी, वह भी मनोपली प्रोक्योरमेंट करना नहीं चाहते । कोई स्टेट में मोनोपली प्रोक्योरमेंट है, कोई में नहीं है । इसलिए मेरा कहना है कि—

"The Uniform policy of compulsory lavy and procurement should be introduced through out the country."

दूसरा सवाल आता है एक्विटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन आफ फूड का । जैसे शहर में आप कहते हैं कि एक लाख या दस लाख की पापूलेशन पर टोटल राशनिंग करेंगे, लेकिन जो किसान अनाज पैदा करता है उसके पास आज अपने बच्चों को देने के लिए अनाज नहीं है । तो वहां क्यों नहीं राशनिंग करते ? देहात में भी अनाज मिलना चाहिए और शहरों में भी अनाज मिलना चाहिए और एक्विटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए । और यह जो फूड का बिजनेस है यह भी प्राईवेट ट्रेडर्स के हाथ में नहीं देना चाहिए । यह बिजनस गवर्नमेन्ट को लेना चाहिए ।

Mr. Chairman: Please conclude now.

श्री दे० शि० पाटिल : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे टाईम दिया । मैं जानता हूं कि यह जो प्वाइंट्स मैंने रखे हैं उन पर सरकार ध्यान देगी ।

Shri S. B. Patil: Mr. Chairman, Sir,..........

श्री विश्राम प्रसाद : सब कांग्रेस वाले बोल लेंगे तब हमको मौका मिलेगा ?

Mr. Chairman: Your party has got only two minutes.

Shri Vishram Prasad: Then why don't you tell me so that I can go?

Mr. Chairman: This is not that way. Only two minutes you will get.

श्री यशपाल सिंह : यह तो आफ्टर थाट हुआ जी । पहले यह कहा कि जो लोग बैठे हैं उनको पांच मिनट मिलेगा

श्री विश्राम प्रसाद : आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि दस दस मिनट बोलेंगे फिर पांच मिनट हुआ और अब कहते हैं दो मिनट .....

Mr. Chairman: We are giving according to the time allotted to the groups.

Shri S. B. Patil (Bijapur South): At the outset I am really grateful to the hon. Minister of Food and Agriculture for taking up this important question of food situation in the country in this august House for discussion. I am also thankful to you for giving me an opportunity to express my views on the burning question and I will try my best to examine the real situation as a true and practical agriculturist, mainly from the practical point of view.

In morning's papers there is a news under the headline 'Ministers just rubber stamps' and I quote from that news item:

> "Union Food Minister C. Subramaniam today listed some major features of the present administrative structure which are impeding the country's progress. He said that a Minister has no choice but to function as a rubber stamp of the department because only the 'final' scheme without any alternative proposals is placed before him. He thus has no alternative except to agree with the proposal before him."

There is another point he made:

> "75 per cent of the officials in the Union Food Ministry had neither any agricultural background nor a rural outlook."

That is one point in regard to the failure of food and agricultural policies of Government.

There is another point also, and that is also worth quoting. I may refer to what the American Ambassador, Mr. Chester Bowles, said regarding the food problem. He said:

> "Land in equality is a bottleneck clogging the creative energy of the people; a bottleneck that must be broken."

He further said:

> "Land reforms are not the solution, of course; it is the first essential step to agricultural improvement; to consolidate fragmented holdings and the development of rural co-operatives and the speedy execution of land reforms programmes is vital for increasing agricultural production and strengthening the base of the rural economy."

These are the two important bottlenecks straining the great energy of the country. Therefore, the country is passing through a food crisis as never experienced before. Soaring prices of foodgrains have rendered existence a burden to the common man. Experts, the State Governments and the Central Government and the Planning Commission are devoting their long and protracted thinking hours to this important matter, but the question still defies solution. It is necessary to give a cool throught as to where exactly the malady exists and how best to remove the sour

[Shri S. B. Patil]

spot so that agriculture marches ahead, healthy and radiant, on the onward path of progress spreading prosperity everywhere in the country.

We must recognise one basic fact that a good harvest is no longer a natural phanomanon. It is a result of sustained efforts. In fact, it is human performance. Unless we recognise this fundamental fact, we are likely to err in our planning.

According to the Food Minister, the yield may be less than eighty million tons as compared to last year. If we add the six or seven million tons of imports under PL 480, the deficiency adds up to 14 to 15 million tons. This is nearly one-fourth of the food available for consumption. This proportion has even worse implication. In the first place, the rich people and the producers will not reduce their consumption; and the deficiency for the rest may rise to one half. Secondly, as there are restrictions or movement of foodgrains between States, and even districts, the deficiency may be higher. For instance, my State of Mysore estimates this year only 50 per cent yield, when even normally there is a five per cent deficiency.

Thirdly, the forecasts of famine will increase hoarding and under the most wasteful conditions, hoarders will try to escape detection by Government and even by starving mobs.

Our objective must be to achieve self-sufficiency in food within our country within limited resources of our own, in order to feed our population and build up a nation which is healthier and stronger. Dependence on PL 480 imports is not only bad for this country, bad for the economic development of the country, but it under mines also our self-confidence and self-respect. The country has to stand on its own legs and a beginning has to be made now towards self-sufficiency.

Productivity per acre in agriculture in our country is about one-fourth or one fifth of what is obtaining in other advanced countries. During the three five year Plans we have increased our production of cereals by only 30 million tons. The index of agricultural production as a whole shows an average annual rise of three per cent only. But the population has been growing at the rate of 2.2 to 2.4 per cent. The level of productivity in Indian agriculture is not comparable with the advanced countries of the world. For example, in regard to wheat, the farmers in West Germany are producing 34 quintals per hectare; a hestare is about two and a half acres; UK, 43.5 quintals per hectare; India, 8.9; Japan, 25.0; the world average comes to 12.6 quintals per hectare.

In regard to rice, we are producing only 13.8 quintals per hectare; the world average is 19.9 quintals. Italy produces 54.9 quintals, USA, 41.8, UAR, 58.8, Australia, 60.0, per hectare. There are various factors affecting the agricultural production in our country. Under the present circumstances, and under the present system of production, skill plays an important role. Risks and uncertainties inherent in agriculture are factors to be reckoned with. There are three kinds of risks—price risk, weather risk and technical risk. The existence of these three risks governs the cost and flow of credit, which in turn governs investment in agriculture.

Lastly, I submit that food must be treated as a national subject and the whole nation must be treated as one zone. No one should have the right to hold up others. Unless energetic steps are taken to deal with agricultural lag and spiralling of essential commodity prices, the entire country would be engulfed in a catastrophe.

श्री बालगोविन्द वर्मा (खेरी) : सभापति महोदय, तीन दिनों से खाद्य समस्या पर विचार हो रहा है । लोगों ने अपने विचार भी रखे हैं । इस में कोई शक नहीं है कि खाद्य समस्या बहुत ही विषम है और उस के बारे में विशेष ध्यान देने की जरूरत है । लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि मंत्री महोदय को सदन में इस समय खाद्य पर खाद्य समस्या को लाना चाहिए था, विवाद के लिए ।

गांवों के अन्दर बड़ा जोर है । किसान हर तरह से और हर जगह को जोत करके अन्न उत्पादन करना चाहता है और वह चाहता है कि सेल्फ सफीशेंट बने । लेकिन यहां से जो डिसकशन का समाचार गावों में जाएगा उसका असर उसके ऊपर जरूर होगा । अगर उसको यह पता चलेगा कि इस रोग का इलाज उसके हाथ का नहीं है तो उसके प्रयत्नों में शिथिलता आ जाना स्वाभाविक है । यदि मंत्री महोदय को लोगों का विश्वास प्राप्त करना था तो वे विरोधी दलों के लोगों को और अन्य सदस्यों को अलग से बुला कर उनसे विचार विनिमयय कर सकते थे, न कि सदन में इस विषय को लाकर इस पर बहस होनी । लेकिन चूंकि यह चीज आ गयी है, इस लिए मैं भी इस पर अपने विचार रखना चाहता हूं । मेरे लिए भी ऐसा करना जरूरी हो गया है ।

कृषि की उन्नति के लिए कुछ बातों की विशेष जरूरत है । मैं समझता हूं कि पहली बात तो यह है कि विभिन्न मंत्रालयों में को-आरडिनेशन नहीं है । इरिगेशन एण्ड पावर, खाद्य और कृषि मंत्रालय और कम्युनिटी डेवेलपमेंट तथा कोआपरेशन का मंत्रालय अलग अलग काम कर रहे हैं । यदि वास्तव में खाद्य समस्या को हल करना है तो कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत ही इरिगेशन एंड पावर, तथा कम्युनिटी डेवेलपमेंट और कोआपरेशन के मंत्रालयों को काम करना चाहिए । यह बहुत जरूरी है । जब तक ये विभाग अलग अलग काम करेंगे तब तक कृषि की उन्नति नहीं हो सकती है । इस लिए गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देकर इसके लिए कुछ करना चाहिए ताकि समस्या का हल निकल सके ।

इसके बाद मैं मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि कुछ गलतियां हम कर रहे हैं जिनके कारण हमारी खाद्य समस्या हल नहीं हो पाई है । जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, हमको छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये जो ऋण मिलता है उसका 35 परसेंट खाद के लिए मजबूरन देना पड़ता है । अगर किसान के पास रुपया हो तो वह कर्ज ही क्यों लेगा ? अगर उसने ट्यूब वेल बनाने के लिये कर्जा लिया है और उसका 35 परसेंट उसको खाद के लिए देना पड़ता है तो उसका परिणाम यह होता है कि ट्यूब वेल नहीं बन सकता, भले ही वह रुपया और किसी रूप में खर्च हो जाए । आज यह गवर्नमेंट की पालिसी है ।

इसके अलावा आप देखें कि उद्योगों के लिए बिजली दो या तीन पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाती है । आप कृषि को भी एक उद्योग मानते हैं, इसके बिना आप तरक्की नहीं कर सकते । यह बेसिक उद्योग है । लेकिन फिर भी कृषि के लिए जो बिजली दी जाती है उसका रेट उद्योग को दी जाने वाली बिजली से दुगना तिगुना रखा जाता है । अगर आप चाहते हैं कृषि की भी उन्नति हो तो आपको कृषि को भी अन्य उद्योगों के तरह ही इसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा ।

इसके अलावा कृषि यंत्रों को देखें । जिस यंत्र में पचास रुपये का लोहा लगता है उसका मूल्य पांच सौ रुपया रखा गया है, यानी बनवाई का 450 रुपया लग जाता है । इस तरह कैसे कृषि की उन्नति हो सकती है ।

रूस का जो 14 हार्स पावर का ट्रैक्टर 5000 में आता है और 25 हार्स पावर का

[श्री बाल गोबिन्द वर्मा]

जो ट्रेक्टर 9000 में आता है उन पर आपने चार और पांच हजार ड्यूटी लगा दी है। इसके मानी यह है कि आप चाहते हैं कि कृषि की उन्नति न हो पाए। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप इंडीजिनिस मैटीरीयल से ट्रेक्टर बनवाईए और उस माल पर एक्साईज ड्यूटी छोड़िए। रशन ट्रेक्टर के बारे में यह जो कदम उठाय जा रहा है, न मालूम इसकी क्या वजह है। हो सकता है कि हमारे यहां के किसी मैनुफक्चरर को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा हो। अगर ऐसा किया गया, तो यह एक बहुत गलत स्टेप होगा। इस लिए सरकार को ट्रेक्टर्ज की ड्यूटी बढ़ाने का इरादा छोड़ देना चाहिए और इस की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए।

जिन लोगों ने ट्रेक्टर्ज खरीदे हुए हैं उन को स्पेयर पार्टस नहीं मिलते हैं। जब को ट्रेक्टर टूट जाता है, तो उस को बनाने की कोई सुविधा नहीं है। मैंने बजट सेशन के अवसर पर भी यह अनुरोध किया था कि जिन जगहों में मैकेनाईज्ड फार्मिंग हो रहा है, वहां पर ट्रेक्टर्ज के वर्कशाप खोले जायें, जहां पर सस्ते दामों पर ट्रेक्टर्ज को रिपेयर किया जाये और उन के स्पयर पार्टस उपलब्ध किये जायें। इसके अलावा ट्रेक्टर्ज को चलाने के लिये सरकार को डोजल आयल, मोबिल आयल और केरोसीन आयल की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अगर सरकार उन पर रेस्ट्रि-क्शन लगायेगी तो काम नही चलेगा।

आज स्थिति यह है कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है, जो कि कृषि के लिए सहायक सिद्ध हो और जिस से खाद्य समस्या हल हो।

प्रोक्युरमेंट की पालिसी बहुत डिफ़ेक्टिव है। सरकार व्यापारियों को कहती है कि वे किसानों से गल्ला खरीदे, जिस में से हम केवल बीस फ़ीसदी लेंगे। इसका नतीजा क्या होता है? उदाहरण के लिये हमारे जिले लखीमपुर खेरी में बनिये बीस, बाईस रुपये प्रति मन के सिहाब से मक्का खरीद रहे हैं और अठारह रुपये मन के हिसाब से गवर्नमेंट को दे रहे हैं। मैंने सुना है कि वे लो कहते हैं कि इस प्रकार बीस परसेंट मक्का सस्ते सस्ते दामों पर गवर्नमेंट को देने से दो चार हजार रुपये का जो नुकसान हो जायेगा, वह नुक्सान तो बाकी का मक्का ज्यादा दामों पर बेचने से पूरा हो ही जायेगा, बल्कि और भी बहुत मुनाफा होगा, क्योंकि, जैसा कि गवर्नमट खुद एडमिट करती है, खाद्य स्थिति खराब होने जा रही है, इस लिए वे बनिये बाकी के मक्के को बहुत ऊंचे दामों पर बेच सकेंगे।

इस लिए यह आवश्यक है कि सरकार प्रोक्युरमेंट के सारे काम को पूर्णतया अपने हाथ में ले। इस को मध्यस्थों के हाथ में छोड़ देना सब बड़ी गलती होगी। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट और मंत्री महोदय इन बातों की और विशेष ध्यान देंगे, ताकि हमारी खाद्य समस्या जल्दी हल हो सके।

सभापति महोदय : श्री यशपाल सिंह।

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति महोदय, हमारी पार्टी का नम्बर पहले आना चाहिए और इन का बाद में आना चाहिए। यह तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम इस को सहन नही कर सकते। पहला नम्बर हमारा है। इस लिए पहले हम को मौका दीजिए और बाद में इन को दीजिए।

Mr. Chairman: Now he has caught my eye. I will give a chance to his party also. The hon. Member may resume his seat.

श्री यशपाल सिंह : सभापति महोदय, जो कुछ इन तीन चार दिनों में कहा गया है,

उन में बहुत सी ऐसी बात हैं, जिन का किताबों के साथ ताल्लुक है, कागजों के साथ तालुल्क है, लेकिन फूड प्राबलम के साथ उन का किसी तरह का सम्बन्ध नहीं है ।

यू० पी० कांग्रेस कमेटी के जेनेरल सैक्रेटरी ने कहा है कि पचास फ़ीसदी ट्यूबवेल इस लिए बन्द हो गए हैं कि उन के आपरेटर्ज की तन्ख्वाह कम है, उन को वहां पर रिश्वत नहीं मिलती है, वे वहां पर रहना नहीं चाहते और इस लिए वे ट्यूबवैल्ज कों बन्द कर के चले गए हैं। यह किसी मामूली आदमी का बयान नहीं है । यह यू० पी० सी० सी० के जेनेरल सेक्रेटरी का बयान है । जो बातें कही जाती हैं, उन का कोई प्रैक्टिकल मूल्य होना चाहिए, प्रैक्टिकल वैल्यु होनी चाहिए ।

प्रश्न यह है कि इस देश में, जहां 85 फ़ीसदी लोग खेती करते हैं, लोगों का पेट क्यों नहीं भरता है और लोग क्यों भूखे हैं । इस का कारण अभी समझ में नहीं आया है । यह अखबारों पर छोड़ दिया गया है । सब से पहले यह जरूरी है कि यह काम आई० सी० एस० अफसरों से छीना जाये । वे खुद भी कुछ नहीं करते हैं और अपने मातहतान को भी नहीं करने देते हैं । मैंने खुद देखा है कि एक आई सी० एस० आफ़िसर के बंगले पर पचास किसान गए और कहा कि हमारे ग्यारह मील के इलाके में ओला पड़ गया है, फ़सलें खत्म हो गई हैं, आप चल कर देखिए। उस आई० सी० एस० कलेक्टर साहब ने कहा कि तुम बगैर एपांयटमेंट लिये हुए आये हो, तुम को जेलखाने में बन्द कर दिया जाये । वे लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि खेती करने वाले को किस चीज की जरूरत है । यह एक बहुत मोटी बात है, लेकिन लोग इस को नहीं समझते हैं ।

आज हालत यह है कि जो लोग खेती नहीं कर सकते, उन को जमीन दीजा री है । बिड़ला साहब को तीस हजार एकड़ जमीन इस लिए दी जा रही है कि वह सीड इम्परूव करेंगे । जिस के बाप ने कभी खेती नहीं की, उसे यह जमीन दी जा रही है कि वह सीड इम्परूव करेंगे ।

Mr. Chairman: The hon. Member should use dignified language.

श्री यशपाल सिंह: यह कोई अनपालिया-मेंटरी बात नहीं है । उन्होंने वाकई खेती नहीं की है । वह बड़े आदमी हैं । वैसे अगर आप कहें, तो मैं ये शब्द नहीं कहूंगा ।

ऐसे लोगों को इतनी ज्यादा जमीन दी जा रही है, और जो खेती कर सकते हैं, वे एक एक बीघा जमीन को तरस रहे हैं

सरकार के कहने के मुताबिक हमारे देश में पचास करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है, जिस में खेती होती है । सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक चालीस हजार ट्रेक्टर हैं, जिन में से बाइस-हजार खराब पड़े हुए हैं और सिर्फ अठारह हजार काम करने के काबिल हैं । इस के अलावा हमारे यहां ढाई हजार बैलों की जोड़ियां हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये अठारह हजार ट्रेक्टर और ढाई हजार बैलों की जोड़ियां तो पचास करोड़ एकड़ जमीन की परिक्रमा भी नहीं कर सकती हैं उस जमीन के चारों तरफ घूम भी नहीं सकती हैं, उस में पैदावार करना तो अलग बात हैं ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि लेंड्ज मस्ट गो टु दि टिलर । जब तक लेंडलैस लेबरर्ज को खेतों पर अधिकार नहीं दिया जायेगा जब तक आई० सी० एस० आफ़िसर्ज को खेती के महकमे से नहीं निकाला जायेगा, जब तक मिनिस्टर लोग किसानों की समस्याओं और कठिनाइयों का पता लगाने के लिए गांव गांव में नहीं जायेंगे, तब तक खाद्य की समस्या हल नहीं हो सकती है । जब चव्हाण साहब डिफ़ेंस

[श्री यशपाल सिंह]

मिनिस्ट्री में डिपुटी मिनिस्टर थे तो वह उस वक्त गांव गांव में जा कर सिपाहियों के घरों में उन को श्रद्धांजलि पेश करते थे, जब कि लू चलती थी, कोई बाहर निकलना पसन्द नहीं करता था—तब वह पांच पांच मील पैदल चलते थे और पसीना पसीना होने के बावजूद अपना फर्ज पूरा करते थे। अगर इस मंत्रालय के मंत्री और अफसर गांवों में घर घर जा कर काम करेंगे, तभी इस देश का निस्तार होगा।

मद्रास में सरकार ने एक फूड कार्पोरेशन खाद्य निगम, बनाया, जो कि फेल हो गया। उस के हाथ से फूड डीस्ट्रिब्यूशन का काम छीन लिया गया और राशनिंग डिपार्टमेंट को दिया गया और दिल्ली में सरकार नई व्यवस्था कायम करने जा रही है। जो चीज मद्रास में फेल हो चुकी है, वह दिल्ली में कैसे कामयाब हो सकती है ? बीच का बनिया छः आने बोरी पर कमाया करता था और आज सरकार तीन रुपये बोरी पर लेगी। ये दो रुपये और दस आने किस के जिम्मे पड़ेंगे ? ये कन्ज्यूमर के जिम्मे पड़ेंगे।

आज जेलखाने के कैदी को हफ्ते में छः किलो राशन मिलता है, जब कि भारत के श्रेष्ठ नागरिक को सिर्फ दो किलो राशन मिलता है। इस तरह काम कैसे चलेगा ?

इस समस्या का सीधा सा हल यह है कि किसान को मौका दिया जाये। जो लोग खेती कर सकते हैं, उन को खेती करने का हक दिया जाये और जो लोग नहीं कर सकते हैं, उन से जमीन छीन ली जाये। जो लोग आज भी पाकिस्तान की इमदाद कर रहे हैं, उन से पूछा जाये कि वे पाकिस्तान की इमदाद क्यों कर रहे हैं, क्यों देशद्रोह का काम कर रहे हैं। दिल्ली क्लाथ मिल्ज के मालिक, लाला भरत राम चरत राम, ने हिन्दुस्तान के नैशनल डिफेंस फंड में एक लाख रुपया दिया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के नैशनल डिफेंस फंड में बीस लाख रुपये दिये हैं। करोड़पतियों की जो कोई भी फर्म है, वह आज पाकिस्तान की इमदाद कर रही है, देशद्रोह कर रही है। अगर इन से जमीन छीन कर गरीब आदमियों को मौका दिया जाये तो यह मामला छः महीने में हल हो सकता है, लेकिन सरकार इसको करना नहीं चाहती।

आखिर में मेरी रिक्वस्ट है कि माननीय सदस्यों को बोलने के लिये पूरा टाइम दिया जाये। यह बहस बार बार नहीं आयेगी। जब हम कहते है कि **वर्क इज वरशिप** तो फिर चाहे आधी रात तक बैठना पड़े माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिये—पूरा टाइम दिया जाना चाहिये, ताकि इस विषय पर पूरी तरह से डिस्कशन हो सके, हालांकि मुझे कम टाइम दिया गया है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : सभापति महोदय, प्रधान मंत्री ने जब यह नारा दिया कि "जय जवान, जय किसान" तो उस को सुन कर मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन ये दूसरे नारे सुन कर मुझे बहुत क्लेश होता है कि 'पानी ले गया पाकिस्तान, प्यासा रह गया राजस्थान" और "फैसला कर गये जवाहरलाल, भूखे रह गये राजस्थान के ग्वाल बाल" ये नारे बड़े खतरनाक हैं। फैसला करने वाले चले गये लेकिन आज राजस्थान की जनता उनको रो रही है, भूखी और प्यासी मर रही है।

हमारी सरकार ने राजस्थान की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के समय वहां पर धड़ाधड़ बम गिराये थे, लेकिन कोई मंत्री

वहां नहीं गया। आज राजस्थान में अकाल पड़ रहा है और इस लिये योजना आयोग से 48 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है, लेकिन वह कहता है कि हम 24 करोड़ रुपये देंगे। इसके अलावा राजस्थान 12 करोड़ रुपये देगा, तो बाकी के 12 करोड़ रुपये कौन देगा? इस तरह से राजस्थान को सब से पीछे छोड़ रखा है। अगर राजस्थान कैनाल केन्द्र के हाथ में होती, तो राजस्थान को इतना दुख न झेलना पड़ता। राणा प्रताप सागर बांध पर 80 करोड़ रुपये लगे हैं, लेकिन उस में पानी की एक बूंद भी नहीं है। इस से वहां पर रात को अंधेरा और दिन को उजाला नजर आता है।

किसानों को जो बीज दिये गये हैं, उन में उर्वरक का पाउडर मिला दिया गया है। सरकार की तरफ से किसानों को कहा गया है कि अगर वे इस बीज को लगायेंगे, तो उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दिया जायेगा। सरकार ने किसानों को फुटबाल बना रखा है। पहले उन को कहा गया है कि गन्ना बोओ, ताकि हम शक्कर के द्वारा विदेशी मुद्रा कमा सकें। जब किसानों ने गन्ना लगाया, तो उन के लिये पानी नहीं है। मैं समझता हूं कि यह सरकार और कृषि मंत्री खाद्य के मामले में बिल्कुल निर्बोध हैं। इनको ज्ञान नहीं है। हमारे कृषि मंत्री ने पता नहीं कौन सी कृषि की विद्या पढ़ी है। पता नहीं किस किस तरह की योजनायें बनाई जाती हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि गमलों और जंगलों में खेती करो उनके अन्दर साग सब्जी बोओ जब कोई इस तरह से करता है तो नगर निगम वाले कहते हैं कि तुम ने पानी खेती में इस्तेमाल किया है, तुम्हारा चालान करते हैं। इस आधार पर कई चालान दिल्ली में किये गये हैं। कारण यह था कि पीने के पानी से साग सब्जी पैदा कर ली है। बेचारी जनता करे तो क्या करे। किस का वह कहना माने। कोई कहता है कि गमलों और बंगलों में खेती करो बागीचों के अन्दर खेती करो और दूसरा कहता है कि पीने के लिए पानी तो है नहीं, तुम खेती के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा चालान किया जाता है। यह ठीक नहीं है। आज तो ऐसा मालूम होता है कि ईश्वर भी हम से रूठ गया है। हमारे यहां राजस्थान के अन्दर झाड़ियां तक सूखी पड़ी हैं जिन को खा कर बेचारे जानवर जीवित रहते थे। आज वहां लोग अपने जानवरों को बाहर ले जा रहे हैं उन को बेच बेच कर अपना गुजारा कर रहे हैं। आज जिन बेचारों के घर में अनाज पैदा भी नहीं हुआ है उन से हमारे यहां कहा जाता है कि सुधार कर लाओ। बच्चा पैदा हुआ ही नहीं नाम पहले ही रख दिया गया है। जिन के यहां नहर का पानी पहुंचा तक नहीं है, जिन को अपनी फसल के लिए पानी दिया तक नहीं गया है उन से वहां कहते हैं कि सुधार कर लाओ, तीस रुपया बीघा और लाओ। यह सरकार क्या करेगी? यह सरकार तो खुद ब्लैक मारकेटिंग करती है, चालीस रुपये क्विंटल के हिसाब से चना खरीदती है और अस्सी रुपये क्विंटल के हिसाब से बेच देती है। यही मध्य प्रदेश की सरकार का हाल है और यही राजस्थान सरकार का हाल है। वहां पर खाने के लिए तो है नहीं लेकिन उसको बाहर भेज देते हैं। किस तरह से सरकार चलेगी?

1952 में हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर था जैसे जैसे इस पर इस हाउस में विचार होता जाता है वैसे वैसे आयात का बोझ और बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम कमी अनुभव करते जाते हैं। यह कहा जाता है कि इस साल 262 करोड़ रुपये का अनाज मंगाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि 262 करोड़ रुपया अगर किसानों को

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

दिया जाये तो हमारी अन्न की समस्या हल हो सकती है । एक साल के लिए अगर जितने आपके निर्माण कार्य हैं उनको बन्द कर दिया जाय, दिल्ली में ही अगर इनको रोक दिया जाये तो हमारा देश आत्मनिर्भर अन्न के मामले में हो सकता है । दो दो और तीन तीन करोड़ रुपया खर्च करके महल खड़े किये जाते हैं, उन में अफसर लोगों के आराम के सभी साधन मुहैया किये जाते हैं, उनके पैरों में धूल न लग जाये, इसका इंतजाम किया जाता है, उनकी पैंट्स की सलवटें खराब न हो जायं, इसकी व्यवस्था की जाती है लेकिन किसानों को कहा जाता है कि लगान लाओ चाहे भूखों मर जाओ, कोई परवाह नहीं है । अगर निर्माण के ये कार्य बन्द कर दिये जाये और किसानों को यह सब पैसा दे दिया जाये तो हमारी अन्न की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है ।

आप ने सहकारिता चला दी है । वहां पर लठ चल रहे हैं । एक काम करता है तो दूसरा नहीं करता है, दूसरा करता है तो तीसरा सो जाता है ।

आप ने जो पट्टे दिये हैं उनको आप देखें । आप ने उनको जेली करार दे दिया है । राजस्थान के अन्दर किसी किसान से पूछा जाता है कि आप को पट्टा मिल गया है तो उसका जवाब होता है कि हमें जेली करार दे दिया गया है, न मालूम कब छीन ले सरकार ।

कृषि फार्म जो सरकार बनाती है उनको आप देखें । कोटा में पांच मील की दूरी पर एक कृषि रिसर्च फार्म खोला गया है । कम से कम दो सौ किसानों को वहां उजाड़ दिया गया है । उनकी खड़ी ज्वार की फसल काट ली गई है । अब वे आये और खड़े हो गये तो उनको लठ दिखा कर भगा दिया गया । अब उस फार्म में एक तरफ ज्वार काटने जाते है और दूसरी तरफ गेहूं बोते जाते हैं । इस फार्म को कहीं जंगल में भेज देते हैं और कह देते कि वहां जंगल की भूमि को अच्छा करो तो कुछ फायदा भी होता । इस तरह के फार्म्स में जो अनाज होता है वह पता नहीं कहां जाता है । अफसरों के घरों में ही वह जाता होगा । एक भी फार्म लाभ में नहीं चल रहा है । सारे नुक्सान में चल रहे हैं । किसानों को उजाड़ करके फिर रिसर्च करना यह कौन सी गवर्नमेंट का कायदा है, यह कहां की अक्लमंदी है, अच्छा नहीं किया ।

आप देखें कि राजस्थान में किसान का क्या हाल है उसके लिए पानी का क्या इंतजाम है । वहां अगर तीन इंच पानी भी बरस जाये तो वे समझते हैं कि परमात्मा धरती पर उतर आया है । लेकिन तीन इंच भी पानी वहां नहीं बरसता है साल में । उनके लिए भी कुछ किया जाये, उनके कुओं को भी गहरा करवाया जाये । एक योजना बनाई गई थी जिसके तहत गत वर्ष सात आठ ट्यूबवैल लगाये गये थे । उसके बाद कुछ नहीं किया गया है । जो ग्रिड थी उसको गुजरात में भेज दिया गया और उनके कुएं अधूरे पड़े हुए हैं, ट्यूबवैल अधूरे पड़ हुए हैं । सरकार तो सुख की नींद सोती है । वह जागती ही नहीं है । लेकिन जो जनता है, जो आम आदमी हैं वे पिस रहे हैं सरकार उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देती है । मैं आप को चेतावनी देना चाहता हूं कि यही हाल रहा तो राजस्थान का जो इलाका है वह उजड़ कर बरबाद हो जायेगा । वहां जमीन सोना उगलती थी लेकिन अब वहां की मिट्टी खराब हो रही है । सोने का कथीर बन रहा है । राजस्थान की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वहां की भूमि बरबाद हो जायेगी । अगर आप राजस्थान को पानी दे दें और बिजली की सुविधायें उपलब्ध कर दें तो राजस्थान सारे देश को अन्न पैदा करके दे सकता है और जो अन्न की कमी है, उसको वह पूरा कर सकता है । यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं ।

Shri M. L. Jadhav (Malegaon): In Maharashtra the monsoon was late—the monsoon in September and October did not come. Therefore, there is a heavy drought in Maharashtra and this has resulted in increase in prices and shortage of foodstuffs. We find that the markets, the weekly bazaars, are full of cattle and the cattle prices have gone down to such an extent that nobody is prepared to purchase cattle in the market. There is shortage of food, there is shortage of fodder and there is likely to be shortage of drinking water also. These are the three problems which were never faced in the State. For the last 100 years such a drought was not there. It can only be compared with the Bengal of 1943. What happened in Bengal in 1943 can be said to be the present situation in Maharashtra. To meet this, it is very necessary that the Centre should come to the help of Maharashtra; not only more food should be given, but it is necessary that fodder should also be given for the cattle. At the same time efforts should be made to provide for more irrigational projects. In Maharashtra there is only 5% of irrigation, including that of well. When we take into consideration the irrigation with canals it is very necessary that this 5% irrigation should be increased. It is very necessary that efforts are made to have medium, minor and major irrigation schemes in this drought-affected area because it can provide relief to the famine-stricken people; it can also help to save future droughts; it may also help to remove the hardships that are being caused by this drought to the people of Maharashtra.

It has been said by the revered member, Dr. Aney, that, because foodstuffs were removed from Vidharba to Bombay, there has been shortage in Vidharba. I am sorry to say that this state of affairs is not correct. For Bombay separate quota has been provided by the Centre and Bombay is fed by the Centre. I say that drought is everywhere; it is not only in Vidharba, but it is also in Maharashtra. The whole of Maharashtra is affected by drought. Therefore, we find that there is shortage of food; there is price increase. There was an argument that it was because the States were formed on a linguistic basis. But I would submit that there is no room for that.

When there is drought, we find that there is shortage of oil; we find that people are not getting oil and a number of diesel pumps are lying idle because of shortage of oil in Maharashtra. I think it is for the Government to supply this oil; it is for the Government to see that pumps do not remain idle and whatever efforts are made to raise *rabi* crop, these efforts should be helped by supplying necessary oil for the pumps.

I find that the charges for the machinery have gone up. These merchants are trying to have blackmarket with respect to some of the machines which are not readily given to the cultivators. Therefore, it is very necessary that Government enters the market and sees that the cultivators get these machines. When there is shortage of food, short term measures such as supply of oil and supply of machines are very necessary to overcome the drought. Therefore, I appeal that the Centre should come to the help of Maharashtra, which is very much affected by the drought, by supplying food and fodder. When we say that P. L. 480 should be stopped, I say that it should be stopped when we can be self-supporting in food. When there is drought, when there is shortage of food in the country, how can we stop the P. L. 480? In the long run, of course, we cannot depend on P. L. 480 or on any other source of supply from any other country because we cannot afford to be beggars. But at the same time, when we are in difficulty, when we are short of food, it is very necessary that we approach the U.S.A. and some other countries and try to get foodstuffs from them.

With these remarks, I conclude.

श्रीमती लक्ष्मीबाई : सभापति महोदय, इस एग्रीकल्चर पर हर सेशन में चर्चा होती है, और सब लोग सुनते चले जाते हैं। हमारे यहां बड़ी बड़ी प्लेन्स बनती हैं लेकिन कागज पर ही रक्खी रहती हैं। लेकिन यह जिम्मेदारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरों की हैं। वे कहां के रहने वाले हैं, यहां के बच्चे हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह यह क्यों नहीं सोचते। इस डिपार्टमेंट में दो सेक्रेटरी होते हैं जिन की तनख्वाह चार चार हजार रुपये होती है, एक स्पेशल सेक्रेटरी होता है, जिस की तनख्वाह चार हजार रुपये होती है, छः ज्वाइन्ट सेक्रेटरीज हैं, बारह डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, इस तरह से कुल मिला कर 43 अफसर हैं जिन की तनख्वाह लाखों रुपये बनती है। मेरी समझ में नहीं आता कि यहां पर माननीय सदस्य जो सजेशन दे रहे हैं उनका वे लोग क्या करते हैं। क्या उन सजेशन्स को पुट्टी में दाखिल कर देते हैं। उन को जो कुछ नहीं मालूम होता उस को उन्हें इन सजेशन्स से जान लेना चाहिये। इन को उन्हें पढ़ना चाहिये। यहां पर भी हम तीन दिन से विचार कर रहे हैं। इस बहस पर भी कम से कम दो लाख रुपये खर्च होते हैं। लेकिन यह बहस किस वास्ते होती है यह हमें नहीं मालूम। जब मैं सब देखती हूं तो मुझे जलन होती है। यहां पर इतने लोग भरे हुए हैं और हमारे यहां गांवों में काम करने के लिये नौकर नहीं मिलते। मैं गांव से आती हूं और चालीस एकड़ जमीन पर खेती करती हूं। रोज रोती रहती हूं लेकिन काम करने वाला नहीं मिलता।

हम जवानों की इतनी इज्जत करते हैं, उन की पूजा करते हैं, जवानों के लिये लोग प्राण देने को भी तैयार हैं क्योंकि वे हमारे देश के डिफेन्स के लिये इतना काम कर रहे हैं। उन जवानों के लिये हमको खाना उगाना है। लेकिन अठारह साल हो गये हैं हमारी आजादी के। रोज-रोज नये-नये प्लेन्स बनते हैं। हर महीने किताबें लिखी जाती हैं। लेकिन किताबें लिखने से क्या होता है। अगर आप को यह नहीं मालूम तो हम से सुन लीजिये। एग्रिकल्चर का काम बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह से दफ्तर में काम होता है दस बजे से या बारह बजे से और चार बजे वह बन्द हो जाता है इस तरह खेती का काम नहीं चलता। एजूकेशन या इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं और शाम को दफ्तर बन्द कर के चले जाते हैं। लेकिन खेती के लिये तो रोज काम करना पड़ता है और हर वक्त काम करना पड़ता है। जो आदमी खेती का काम करता है उसकी बीवी, बच्चे, बहिन व बैल को भी रात और दिन खेत में काम करना होता है। उस के लिये कोई तातिल नहीं, कोई रुखसत नहीं। जब इस तरह से काम होता है तब जा कर देश में उत्पादन होता है।

यहां पर एग्रिकल्चर वाले बड़े बड़े ओहदेदार बैठे हुए हैं। 2000 लोग कृषि भवन में काम करते हैं। उन के लिये बैठने की जगह तक पूरी नहीं हो रही है, उन के रेकार्ड रखने के लिये जगह भी पूरी नहीं है। नतीजा यह होता है कि कोई काम ठीक से नहीं होता। यह स्टेट सब्जैक्ट नहीं है। सेंट्रल सब्जैक्ट है, तब फिर ये 2000 लोग क्या कर रहे हैं? आप इस चीज पर सिर्फ 2 करोड़ रुपये खर्च करते हैं लेकिन उससे क्या होता है? यह लोग सिर्फ फाइलें तैयार करते हैं। चावल आया, लेकिन चावल इसी तरह से नहीं खा लिया जाता, गेहूं आता है उसकी रोटी बना कर लोग खाना खाते हैं। एग्रिकल्चर वालों को चाहिये कि वहां स्टेट्स में जा कर काम करें। मैं इतने लोगों को नौकरी से नहीं निकलवाना चाहती। लेकिन उन को सोचना चाहिये कि यह बड़ा सीरीयस मैटर है, डिफेन्स से भी बढ़ कर है क्योंकि डिफेन्स की ताकत है अनाज। जवान लोग जंगलों में रह कर और पहाड़ों में रह

कर हमारी रक्षा करते हैं। अगर उन के लिये कोई मुश्किल आती है तो यह हमारे लिये प्रधान चीज हैं । लेकिन इस महकमे की तवज्जह इस की तरफ नहीं है ।

एग्रिकल्चर हमारी मदर इंडस्ट्री है जिससे 31.9 परसेन्ट नेशनल इन्कम होती है । लेकिन उस पर खर्च कुल इनकम का सिर्फ 2 या 3 परसेन्ट होता है। जब इसी तरह एग्रिकल्चर पर कम व्यय चलता रहेगा तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री से कैसे हमको खाना मिल सकेगा । आप काम भी नहीं करते हैं और पैसा भी नहीं देते । अठारह साल इस तरह से चलि गये । लेकिन अब इस तरह से गाड़ी चलने वाली नहीं है ।

मैं आंध्र प्रदेश से आती हूं । हमारे यहां चालीस लाख टन अन्न का उत्पादन होता था, अब वह 30 लाख टन रह गया है । 10 लाख टन कम हो गया है । इस का कारण यह है कि उन लोगों को बड़ी परेशानी है । बरसात भी उन के साथ दुश्मनी कर रही है और पानी नहीं मिलता है । वहां पर लोगों में बड़ी बेचैनी है । आप को जाकर गांवों में घूमना चाहिये और घर घर जा कर किसानों को देखना चाहिये । आज हम को गांवों की क्या हालत देखने को मिल रही है । कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बना रहा है । वे कहते हैं कि हमारे गांवों में यतीम बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो हमारा बच्चा क्यों इतनी मुसीबत उठाये । हमारा बच्चा भी स्कूल जाये । बहुत अच्छी बात है । लेकिन मुश्किल यह है कि आप के स्कूलों में एग्रिकल्चर का काम नहीं सिखलाया जाता । चूंकि इस के लिये वहां लोगों को यहां जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, इसलिये काम नहीं हो पाता है ।

आज फैक्ट्रीज में जो काम करने वाले हैं उन से आप लड़ते नहीं हैं, उनको प्राविडेंट फंड भी देते हैं, इसलिये गांवों के लोग यहां आ रहे हैं। यहां उन के लिये घर होता है, मुलाजिमत होती है, उन को तन्ख्वाह मिलती है, प्राविडेंट फंड मिलता है, लाइट मिलती है, पानी मिलता है और लड़कों के पढ़ने के लिये स्कालरशिप मिलता है, तब गांव में गरीब लोग रह कर क्या करें। गांव में रहने वालों के मकान गिरते रहते हैं। वहां पर कोई सुविधाएं नहीं हैं। वहां पर कौन काम करे। आज गांवों में सिर्फ बुड्ढे या बुड्ढी रह जाते हैं। आज हालत यह हो गई है कि जिन के पास जमीन है वह खुद जा कर काम नहीं करते और जो गरीब हैं उन के पास ऐडवान्स देने के लिये पैसा नहीं है। जिन के पास पैसा है वह खेतों में जा कर काम नहीं करते, नौकरों से काम करवाते हैं। किसान के पास नौकरों को देने के लिये 3 रु० या 4 रु० फी आदमी, पैसा नहीं है। जिसके पास आइस है वह अपना काम करवा लेता है। पूसा इन्स्टिट्यूट में आप रिसर्च के ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन क्या उस से आप को 1 परसेन्ट रिटर्न भी मिलता है? आप एक आदमी को जब 4 रु० रोज देते हैं तो वह आठ बजे सुबह आता है और चार बजे चला जाता है। फिर उस की घरवाली काम करने नहीं आती? मैं नहीं जानती कि सेक्रेटरी को यह पता है या नहीं। मैं गुस्से से नहीं कहना चाहती लेकिन फिर भी इस पर जोर देना चाहती हूं कि आप के 43 अफसर यहां क्या करते हैं। वह देहातों में चले आये अपनी योजनाओं को लेकर। जिस तरह से एक ब्रिगेडियर अपनी फौज को ले कर लड़ने के लिये आता है उसी तरह से आप लोग एक एक स्टेट में अपने आदमियों को लेकर बैठ जाइये और वहां के आदमियों को सिखलाइये कि किस तरह से काम करना चाहिये। एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इस बारे में कोशिश करनी चाहिये और लोगों को सिखलाना चाहिये कि वह ऐग्रिकल्चर के लिये काम करें।

यहां पर रोज रोज रिपोर्ट आती है कि हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ेगा, हम बाहर से गेहूं मंगा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले यह

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

सोचते हैं कि हम आर्डर देंगे और अनाज आ जायेगा । एक सेक्रेटरी यह तय करता है और उस के बाद वह दूसरे महकमे में चला जाता है । और खाली जगह पर जो आता है उसको कुछ पता नहीं रहता । वह आ कर सारी बात को भूल जाता है । लेकिन इस तरह से अब काम नहीं चलेगा । सब से ज्यादा काम ऐग्रिकल्चर डिपार्टमेंट वाले को करना चाहिये जैसे कि किसान किया करता है । ऐग्रिकल्चरल कंट्री में इस तरह से काम न होना मुझे पसन्द नहीं है ।

आप ने चौथी योजना जो बनाई है वह 21,000 करोड़ रुपयों की है । लेकिन मुसीबत यह है कि उस में से आप ने सिंचाई योजना के लिये बहुत कम धन रक्खा है । यहां पर जो नैशनल इनकम होती है उसका 40 परसेन्ट कृषि उत्पादन से आता है । आम तौर से यह होता है कि जिस के यहां चार सेर दूध होता है वह उस में से दो सेर तो अपने यहां रख लेता है बाकी दो सेर की कीमत का उसे चारा आदि खिलाना पड़ता है । लेकिन आप जो 40 या 50 परसेन्ट नैशनल इनकम लेते हैं कृषि को उस में से मुश्किल से 2 या 3 परसेन्ट देते हैं । इस तरह से हमारा काम कैसे बन सकता है ? इतने साल गुजर चुके हैं लेकिन हमारा काम बन नहीं रहा है और न बन सकता है । आप को सावधानी से इस काम को हाथ में लेना चाहिये । आज आप संकट में हैं इसलिए आप को बहुत ध्यान पूर्वक काम करना चाहिये ।

आज देश में राशनिंग की बहुत बात चल रही है । यह कोई अच्छी बात नहीं है । राशनिंग होने पर कुछ बड़े लोग इस में शरीक हो जायेंगे और गल्ला सप्लाई करने का काम शुरू कर देंगे । उन को मालूम है कि यह सरकार तो अन्धी बन कर रहेगी । यह राशन कंट्रोल करेगी और आखीर में लोगों को मुश्किल से तीन या चार छटांक देने लगेगी । तब लोग उन से ही खरीदने तो आयेंगे । मैं ने फूड कारपोरेशन के आंकड़े देखे हैं । मेरे पास समय नहीं है नहीं तो मैं आप को वे आंकड़े बतला देती । यहां पर मैं आ कर सुबह से बैठी रहती हूं लेकिन साढ़े सात बज रहे हैं तब जा कर मुझे टाइम मिला है और वह भी पूरा नहीं मिल पाता ।

सभापति महोदय : आप को पूरा टाइम मिल रहा है ।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : आप को मालूम है कि मैं 125 आदमियों को या 150 आदमियों को खाना खिलाती हूं लेकिन मैं कहीं बाहर से अनाज खरीदती बेचती नहीं हूं । आप श्री पाटिल साहब से पूछ लीजिये, डा० राम सुभग सिंह से पूछ लीजिये । मैं रात दिन काम करती हूं और दूसरों से भी काम कराती हूं । मैं इस तरह की ट्रेनिंग लोगों को दे रही हूं । हम चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में सेल्फ सफिशिएन्सी हो जाये, लेकिन आप के पास कोई व्यवस्था नहीं है । सब से बड़ी लाचारी कीमत की है । चूंकि उन को कीमत नहीं मिलती इस लिये वह लोग कैश क्राप में चले जाते हैं जिस में कम मेहनत लगती है । कोई तम्बाकू उगाता है कोई गन्ना उगाता है । आप को स्टेट वालों को बुला कर इस बारे में कहना चाहिये । जो कैश क्राप होती है उसको आप सबसिडी देते हैं, सब कुछ देते हैं . . .

सभापति महोदय : अब आप खत्म कीजिए ।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : मैं इतना ही अदब से आप से अर्ज करना चाहती हूं कि हमारे ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को रेस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए । जैसे कि डिफेंस वर्क . . .

सभापति महोदय : अब बैठ जाइए ।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : इनका जो फर्टिलाइजर होता है 30 रुपये 35 रुपये में बिकता

था वह अब 100 रु० में मिलता है, तो यह क्या करेंगे

सभापति महोदय : देखिए अब बैठिए ।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : अच्छा, शुक्रिया । इस से आप को सावधान रहना चाहिए ।

Mr. Chairman: Please sit down.

Shri Priya Gupta (Katihar): How much time?

Mr. Chairman: Two minutes.

Shri Priya Gupta: I will take 1½ minutes.

Mr. Chairman: Complete two minutes.

Shri Priya Gupta: I will obey more than what you want me to obey.

It is unfortunate that one cannot even formulate a point in two minutes.

I only wish to ask for certain clarifications of the Minister of Food and Agriculture, whether, first as per the promise of the Prime Minister and the Food Minister to call a conference with the Opposition Members for a long-term solution of the problem, a meeting is going to be called or it is still in the air.

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan): That meeting was called.

Shri Priya Gupta: One meeting was called for short-term policy decision.

Mr. Chairman: The hon. Minister may answer at the time of reply, not now.

Shri Priya Gupta: Secondly, who is responsible for the supply, procurement and other things relating to food problem in India, whether States or Central Government, how are they to be co-ordinated? Until this is decided, all policies adopted here in this House, in all the sub-committees, will never be fruitful.

After 17½ hours of discussion for these three or four days by the supreme body of this nation, we are deciding the fate of 45 crores of people. But we look into the papers and we find that the Minister is going to wind up the debate by his speech and bring a solution. I do not know what solution the Minister will bring tomorrow to indicate that this House has successfully solved the problem.

Kindly remind me when it is two minutes.

Government has opened fair price shops, very nice, but for three months continuously, not a single *dana* of rice has been available anywhere in Asansol, Bongaigaon, Alipur-Buars, Kurseong, Katihar and other places. I have quoted three States, Assam, West Bengal and Bihar.

There is the Food Corporation of India. The Government of India decided on it because the middle people should not be private men, and therefore the Government of India has laid out Rs. 100 crores and set up F.C.I. And who is the Chairman of it? A classfriend of Mr. Subramaniam, Mr. A. T. Pai, and the owner of a bank. He is a business magnate. He has been put in charge as Chairman of the Corporation. And there the appointments are made very nicely! I will not mention the name of the lady, it is Lalita Shethy or somebody who was personal assistant to some officer for six months, promoted in Class II, now recommended for Class I. All nepotism, corruption, *manmani* treatment is going on there in the recruitment policy of the southern zone of F.C.I. Two parallel organisations are running, one in the name of FCI, and another in the name of the Food Ministry of the Government of India. Both are running the same organisation and some of the subjects are transferred to the food corporation of India. There is increase in the total expenditure. Will Mr. Subramaniam take note of it.

[Shri Priya Gupta]

Lastly, about the employees. I am sorry to mention here that the same work—the resolution is there—will be taken over by the FCI, work which is being done by the food department of the government. Why should the service conditions of the employees be curtailed? Why should the protection of article 311 in matters relating to termination or removal of service or dismissed be denied to them? Why should the seniority Rules of Food Department employees not be protected there? Why should not the assurances held out to them in Parliament in respect of service conditions be honoured? I want to know all these clarifications when the Minister replies tomorrow because these are very fundamental things....

Mr. Chairman: You can complete your sentence.

Shri Priya Gupta: Thank you for your mercy. I desire the Minister to kindly keep in mind these points and give replies to them. I will be grateful to him. It will serve the people of India and the hundreds of workers in the southern zone and other zones also who are there. Why cannot the different States be co-ordinated in respect of the working of the FCI?

Shri Bakar Ali Mirza (Warrangal): Many hon. Members of the House suggested that there should be co-ordination between the Food Ministry and the Irrigation Ministry and the Community Development Ministry. In fact, some have suggested that these should be combined into one. Looking at the treasury benches I see that not a single minister representing any of the ministries is present here. Only the Deputy Minister is acting for the whole Cabinet but even he is not taking down any notes. This is not really being fair to the House. Mr. Subramaniam has appealed for co-operation. Surely when the country is facing such a tragic situation, such cooperation is essential. Some people say that scarity reports are exaggerated. I cannot accept that, because in my own constituency of Warrangl and the neighbouring constituency of Khammam and Rayalaseema area there is really failure of crop. Of course in the rice belt things are not so bad. That is the view expressed by Dr. Aney also and some others. Conditions of scarcity are there and we could not but accept the help that any country may give at this time. The point is this. Why are we facing such a situation now? What is the cause? When PL 480 was mentioned in this House the previous Food Minister, Mr. S. K. Patil said that he was going to build a buffer stock. Where is that buffer stock? Even an important minister like Mr. T. T. Krishnamachari said the other day that last year, there was 88.8 million tons record production and that there is still foodgrains in the market with the merchants and the traders. It is not mentioned by anybody who is not fully aware of the statistics and conditions in the country, but by a very responsible Minister. Even when there was a bumper crop and we were also importing under PL 480, how is that not a single ton of grain was put aside as buffer stock? Is it not the responsibility of the food Minister when he has made that commitment while taking that aid for a particular purpose and aim, to adhere to that aim?

Now the problem is that of production. Somebody has said. I do not remember who— that our economy is consumer oriented and not producer oriented. And that is quite true, because if you are thinking of producers then you must take into account those factors which help production. One factor is known all over the world, and that is hig prices. If you give high prices, it acts as an incentive for production, and there is greater production; that incentive is being denied to the cultivator. The reason advanced by Shri Subramaniam is that we have to have rationing and we should take care of the poor; and that if the prices are too high, the poor will

suffer. The peasant also is a poor person. There are more poor peasants than poor people in the cities. If you are thinking of the poor people alone, then I ask you you look at the difference between the poor person in a city and a poor cultivator. The poor person in the city say, a chaprassi can make some more money elsewhere also and become a Jamedar—leave alone all other classes—while a peasant cultivator with half to two acres of land can only get a fixed income; all he has to do or can do is to cultivate his land which may extend, say, five to 10 acres at the most. There is no additional income of any kind and if he has to make any money at all, that is only from the produce from the land, and so, if you fix a ceiling on the price of his produce, it means that you not only seal his fate for a short period but indeed for the rest of the life of the cultivator, the cultivator has absolutely no future. Therefore, if you have this kind of limitation on prices, then your economy is not producer-oriented as far as production is concerned.

I can understand there may be some reasons for having fixed prices and for controlling prices. If you do that you are taking something from the pocket of the poor cultivator, and it becomes necessary for the Government to compensate him in some other way. What other compensation you are giving? A person in the city gets money at a much cheaper rate than the person in the villages, and a person in the city gets things done more quickly than a person in the villages. How are you helping him? Is it not possible to distribute some diesel engines and pumps and so on and make the villagers pay for them in 10 to 15 years' time? Why put so many restrictions and all that? You are spending money on big projects, why did you not in the past give or spend a few hundred crores in giving pumps to the peasants and let them pay back in say 20 years or so. Even if you lose that money, what really do you lose, because production is going to rise, and that is indirect gain.

There is also the State Bank of India. When that was done, there was was converted, into the State Bank of India. When that was done, there was definite commitment that it will help the agriculturists. What help has the State Bank of India given? Nothing at all; practically nothing.

Then I come to one very important point and that is the question of land. As Acharya Kripalani also said, 50 per cent of the land in this country is in the hands of bigger producers, and the other 50 per cent is in the hands of the people who live from hand to mouth. 42 per cent of the cultivators own less than a hectare; that is the Government of India figure. If a person has got only one acre or half an acre, it does not matter what you give him by way of manure, chemical fertilisers, etc.

Mr. Chairman: The hon. Member's time is up.

Shri Bakar Ali Mirza: Two minutes more. Even then, with the increase in production, that will be sufficient only for himself. So, you should not only consider the question of greater production but you must produce a marketable surplus. All these 42 per cent of the cullivators are not producers in that sense; but they are consumers. Therefore, if you want the production really to rise, these small holdings must go. Either you must have consolidation or try co-operative farming—which you know it is a very difficult thing to actually work out. If you cannot do it, then, you must get land from the bigger holders and give land to those who have uneconomic holdings, instead of giving some land to the landless people and asking them to work on it, because in the latter case, it is an uneconomic sort of thing and that is not a production-oriented scheme. All these small plots must be converted into economic holdings and for that there is also a political reason.

In villages today, you find one or two big zamindars—big landlords—

[Shri Bakar Ali Mirza]

who perhaps live in the city and let out their lands on crop-sharing. Crop-sharing is recognised as the worst form of productive method. There is the theory of Mao Tse Tung that the weaker and more numerous party should attack the stronger; the small landlord should attack the big landlord; in turn, the villages should attack the cities. That plan has succeded in China. If you want to prevent communism spreading in this country, you have to see that the villages become simply invulnerable to such an attack. That is only possible if you have a large number of economic holdings and make them take some interest in education, folk dance, etc. and they have some leisure and some savings to use in their development. I will stress on the Food Minister to give more thought to this matter especially when the Planning Commission and other experts also say that the land reforms are not being implemented. The FAO also says that the problem in this country is the neglect of land reforms. America has given a more equitable distribution of land to Japanese cultivators under MacArthur, but in India, we profess socialism, but have not done anything in this matter.

The minister may say it is a State subject. But a party which is committed to this and which is ruling in every State cannot get away making this technical excuse. If there is need for an amendment of the Constitution, amend it and implement this policy.

श्री विश्राम प्रसाद . अभी थोड़ा देर पहले माननीय तिवारी जी ने कहा कि हमारी सरकार खाद्य समस्या के लिए बड़ी चिन्तित है । उस चिन्ता का नमूना यह है कि एक डिप्टी मिनिस्टर यहां बैठे हैं, जो कि पहले ऊंघते रहे और अब गप्पें कर रहे हैं । फुड प्रोडक्शन की बहस के समय सिचाई मंत्री, कम्युनिटी डेवेलपमेंट मंत्री, इंडस्ट्री मंत्री को यहां होना चाहिए था और प्रधान मंत्री को भी यहां होना चाहिए था । लेकिन केवल डिप्टी मिनिस्टर बैठे हैं । यह चिन्ता है सरकार को ।

और मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले 18 सालों में इस सरकार ने जितने भी काम किए हैं सब कागजी हैं । यह कागजी सरकार है । कागज पर प्लान बनाती है और कागज पर ही फुड प्रोडक्शन बढ़ता है । यदि कम्युनिटी डेवेलपमेंट वाले मंत्री, यहां होते और समय होता तो मैं बताता कि किस प्रकार कृषि प्रोडक्शन के आंकड़े बनाये जाते हैं तथा सरकार को बता दिए जाते हैं । हमारे यहां एक मसल है कि अन्धेरपुर नगरी चौपट्ट राजा, टके सेर भाजा टके सेर खाजा । लेकिन मैं तो इस सरकार का महा चौपट्ट कहता हूं । हमारी तरफ आजमगढ़ और गाजीपुर में तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में आम तौर पर आजकल दाल एक रुपया दस आना सेर, एक रुपया छ आना सेर चावल और एक रुपया दो आना सेर गहूं मिल रहा है । यह कागज की नाव कभी नहीं चल सकती और न इससे फुड प्रोडक्शन बढ़ सकता है ।

शास्त्री जी ने कहा कि सोमवार को व्रत रखो, लेकिन शायद शास्त्री जा को पता नहीं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने लोग रोज व्रत रखते हैं । इस गमले और बंगले की खेती से देश का पैदावार नहीं बढ़ने वाली है । अगर आपको किसान द्वारा अन्न का उत्पादन बढ़ाना है तो उसको सस्ता पानी दीजिए, सस्ती बिजली दीजिए । आज हालत यह है कि बिड़ला को तो अल्यूमीनियम प्लांट के लिए तीन पसे यूनिट बिजली दी जाती है और किसान को 19 पसे यूनिट । आप किसान को पानी देते नहीं, बिजली सस्ती देते नहीं तो पैदावार कैसे बढ़े । जैसा कि आपका एडीशनल फूड प्रोडक्शन का यार्डस्टिक है कि अगर आप एक एकड़ जमीन को पानी देने की व्यवस्था करें तो 6 मन पदावार बढ़ सकती है । तो सिचाई की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं करते ?

बाहर से जो रासायनिक खाद आती ह उसका भाव 200 रुपया टन है और सिंदरी में जो खाद बनती है उसकी कीमत 370 रुपया प्रति टन पड़ती है, लेकिन किसान को वह 436 और 440 रुपए टन पर दी जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको खेती की पैदावार बढ़ानी है तो वह हाउस में बैठ कर कागज पर प्लान बनाने से नहीं बढ़गी। आप कृपा करके किसान को पानी दीजिए।

अभी तक जो प्लान चलाये गए हैं जिससे बाहर से कर्जा लिया गया है तथा देश को बारटर किया जा रहा है। जो कम्युनिटी डैवलपमेंट बलाक्स हैं उन पर पिछले दस साल में साढ़ 17 लाख रुपया खर्च किया जाता है। अगर इस से केवल कुंवे, रहट और ट्यूबवेल बनाए गए होते तो ज्यादा पदावार बढ़ गई होती। यह रुपया अधिकतर अफसर आदि रखने पर खर्च किया जाता है।

सभापति महोदय, चूंकि आप ने मुझे केवल दो मिनट का समय दिया है, इसलिए जब दो मिनट हो जायें, तो मझे बता दीजिए ताकि मैं उस से आग न बोलूं।

यू० पी० का हालत यह है कि एक तरफ तो सूखा पड़ा हुआ है और किसानों के खेत में बीज तक नहीं पैदा हुआ है और दूसरी तरफ मिट्टी का तेल बाजार से गायब है—आज वह डेढ़ रुपये बोतल मिलता है। लगान सवाया कर दिया गया है। सुरक्षा फंड के नाम से किसानों से पटवारी अलग रुपया वसूल कर रहा है, ग्राम सेवक अलग वसूल कर रहा है और थानेदार और पुलिस वाले अलग वसूल कर रहे है। आज किसानों की यह हालत है। सरकार प्लानिंग, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना का बार बार जिक्र करता है, लेकिन प्रश्न यह है कि इन योजनाओं से किसानों को अब तक क्या फ़ायदा हुआ है।

जहां तक प्रोक्युरमेंट का सवाल है, सरकार प्रोक्युरमेंट के द्वारा गल्ला प्राप्त कर के शहर वालों को राशनिंग में देगी। लेकिन जिस किसान के पास खेत नहीं हैं, जिसके पास गल्ला नहीं है, वह कहां से गल्ला खरीद कर खायेंग?

अगर किसान की तरक्की करनी है, तो उस को पानी और खाद सस्ती दी जाये, उस का लगान कम हो। जो बड़े बड़े लोग खेती नहीं करते है, जिन के नाम से हजार एकड़ खेत हैं, जिन की एक टांग खेती में है, एक टांग बिजिनेस में और एक टांग नौकरी में है, उन से जमीन छीन ली जाये और असल खेती करने वाले को दी जाये।

श्री बे० शि० पाटिल : क्या वह तीन टांग का आदमी है?

श्री बे०शि० पाटिल : नहीं, तीन आदमी हैं। जो दरअसल खेती करने वाला किसान है, उस को जमीन मिलनी चाहिए।

मैं एक सवाल पूछ कर खत्म कर देता हूं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सरकार किस तारीख तक बाहर से हाथ फला कर गल्ले की भीख मांगना बन्द कर देगा। स्वतंत्रता मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हर साल यही कहा कि इतने सालों में हम अन्न के मामले में सैल्फ-सफ़िशेंट हो जायेंग, लेकिन हम अभी तक हम सैल्फ़-सफ़िशेंट नहीं हो पाये हैं। मैं यह जाना चाहता हूं कि कब हमारा देश खाद्यान्न के बारे में आत्म-निर्भर हो जायेगा। इन अठारह सालों में इस गवर्नमेंट ने क्या पैदावार की है? भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरबाजारी, बेकारी, खाने-पाने के बिना मौतें, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि कब यह देश आत्म-निर्भर होने जा रहा है और कब यह सरकार

[श्री विश्राम प्रसाद]

दूसरों से हाथ फैला कर मांगना बन्द कर देगी ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जब कांग्रेस गवर्नमेंट ख़त्म हो जायेगी, तब ।

Mr. Chairman: I think all hon. Members who wanted to participate have spoken. The discussion on the food situation is over. The hon. Minister will reply to the debate tomorrow.

19.45 hrs.

The Lok Sabha *then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesady, December* 7th, 1965/*Agrahayana* 16, 1887 (*Saka*).

GMGIPND—LS—II—2108 (Ai) LSD —6-1-66—970.